हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर

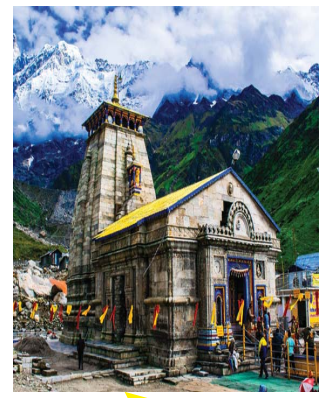

वर्ष:5 अंक:36 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये pathpravah.com हरिद्वार, मंगलवार, 10 फरवरी 2026

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कुंभ मेला-2027 की तैयारियों की समीक्षा

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में कुम्भ मेला-2027, हरिद्वार की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कुंभ से जुड़े सभी कार्य अक्टूबर माह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेला राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसका आयोजन भव्य, दिव्य एवं सफल होना चाहिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अधिकारियों से कहा कि कुंभ क्षेत्र में होने वाले सभी निर्माण कार्य तय समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं और कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि शासन स्तर पर कुंभ से संबंधित कोई भी कार्य लंबित नहीं रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की देरी पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सचिव पीडब्ल्यूडी को 24 घंटे के भीतर कुंभ मेले के लिए तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति

सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कुंभ क्षेत्र में स्थित सभी पुलों का ऑडिट, घाटों का सौंदर्यीकरण एवं आवश्यकतानुसार पुनर्निर्माण कार्य कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि हर की पैड़ी सहित सभी प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम स्नान व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मेला क्षेत्र की स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए विस्तृत कार्य योजना बनाने, पर्याप्त शौचालयों और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल, जल पुलिस की तैनाती, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों सहित आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया गया। उन्होंने कानून व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और पार्किंग के लिए अलग-अलग ठोस कार्य योजनाएं तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ क्षेत्र में अखाड़ों को भूमि आवंटन तय समय पर किया जाए और इसकी सतत निगरानी मेलाधिकारी द्वारा की जाए। उन्होंने अखाड़ों, मठों, संत समाज, धार्मिक संस्थाओं और स्थानीय नागरिकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर उनके सुझावों को तैयारियों में शामिल करने के निर्देश दिए। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुंभ क्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाने पर भी बल दिया गया।

मुख्यमंत्री ने वन विभाग से जुड़े मामलों में शीघ्र अनुमति, अन्य राज्यों के साथ आपसी समन्वय तथा कुंभ से जुड़े सभी विकास कार्यों को धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाने के निर्देश दिए। उन्होंने टेंट सिटी, आवासीय व्यवस्थाओं, अस्थायी अस्पतालों, एम्बुलेंस एवं मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की व्यवस्था समय से पूर्ण करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेला हमारी संस्कृति, आस्था और करोड़ों श्रद्धालुओं से जुड़ा एक महाआयोजन है। इसे सफल बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है, ताकि राज्य में आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु उत्तराखंड से अच्छा अनुभव लेकर जाए।

बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान, रेनू बिष्ट, अनुपमा रावत, रवि बहादुर सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं कुंभ मेलाधिकारी सोनिका सिंह उपस्थित रहीं।

एक नजर

खालिस्तानी धमकियों भरे ईमेल से संसद और दिल्ली के स्कूलों में सुरक्षा अलर्ट जारी

नयी दिल्ली। खालिस्तानी समर्थकों ने दिल्ली में संसद भवन को उड़ाने की धमकी दी है जिसके बाद संसद परिसर के आसपास सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गयी है। सोमवार को दिल्ली के कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भी भेजे गए, जिनमें बम विस्फोटों की चेतावनी दी गई थी और 'हिंदुस्तान बनेगा खालिस्तान' के नारे लिखे हुए थे। ये ईमेल ज़ैकरी जेनकिंस नाम के व्यक्ति ने भेजे थे और भेजने वाले ने धमकी में पंजाबी भाषा का इस्तेमाल किया है। ईमेल में लिखा था, 'दिल्ली खालिस्तान बनेगा। आज शहीद अफजल गुरु की याद में दोपहर 1:11 बजे बम विस्फोट होगा। आज स्कूलों में धमाके होंगे। संसद में बम फटेगा। यह घटना 13 फरवरी को दोपहर 1:11 बजे होगी। मोदी, शाह और जयशंकर खालिस्तान समर्थकों के दुश्मन हैं। पंजाब खालिस्तान है। जिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले हैं, उनमें दिल्ली कैंट का लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल, श्रीनिवासनपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का कैम्ब्रिज स्कूल, रोहिणी का वेंकटेश्वर स्कूल और सीएम स्कूल, सादिक नगर का द इंडियन स्कूल, आईएनए का डीटीए स्कूल और रोहिणी का बाल भारती स्कूल शामिल हैं। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीमें बम निरोधक दस्ते के साथ स्कूलों में पहुंची। सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियात के तौर पर परिसर में तुरंत गहन तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस ने कहा, 'वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल को पूरी तरह से सैनिटाइज़ किया गया है और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। '

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त नोकझोंक के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

नयी दिल्ली। लोकसभा में सदन चलाने के लिए सुलह की बातचीत के बाद भी विपक्ष तथा सत्तापक्ष के बीच सोमवार को जमकर नोकझोंक हुई जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरु हुई और पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने बजट पर चर्चा की शुरुआत कराने के लिए कांग्रेस के डॉ शशि थरूर का नाम लिया। उन्होंने डॉ थरूर का नाम लेते हुए उन्हें बजट पर बोलने के लिए कहा लेकिन डॉ थरूर ने कहा कि विपक्ष के नेता सदन में बोलना चाहते हैं। यह उनका अधिकार है लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। श्रीमती राय ने कहा कि सबको बोलने का अधिकार है लेकिन इस समय सिर्फ बजट पर ही बोलना है। इसी बीच सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि करीब एक घंटा पहले वह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले थे और उन्होंने कहा था कि वह उन्हें सदन में कुछ मुद्दों पर बोलने की अनुमति देंगे लेकिन सदन की कार्यवाही शुरु होते ही सरकार अपनी बात से पीछे हट गई है।

इस पर पीठासीन अधिकारी ने व्यवस्था दी कि सदन में सिर्फ बजट पर ही बोलना है। इसके अलावा आपको अन्य किसी विषय पर नहीं बोल सकते क्योंकि किसी अन्य विषय पर बोलने के लिए आपकी तरफ से कोई नोटिस नहीं है इसलिए आप सिर्फ बजट पर अपनी बात कह सकते हैं। उनका कहना था कि बजट के अलावा किसी और विषय पर सदन में बोलना है तो पहले नोटिस देना पड़ेगा।

संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा 'जिस मुलाकात की बात विपक्ष के नेता कर रहे हैं उस दौरान वह भी अध्यक्ष के कमरे में थे। श्री गांधी के साथ उनकी पार्टी के नेता के सी वेणुगोपाल भी थे लेकिन उस समय अध्यक्ष ने कहा था कि यदि शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलाने पर सहमति बनती है तो बोलने दिया जाएगा। आप जो बोलना चाहते हैं उस पर बोलने की बात नहीं हुई थी। श्री गांधी सदन में इस मुलाकात में हुई बात को लेकर जो कुछ कह रहे हैं ऐसी कोई बात अध्यक्ष के कमरे में नहीं हुई थी। अध्यक्ष ने कहा कि यदि सबकी सहमति बनती है और सदन शांति से चलता है तो देखेंगे। यह बात हुई थी।

चिकित्सा व शैक्षिक पुस्तकों पर जीएसटी को लेकर लोकसभा में उठा मुद्दा

पथ प्रवाह, नई दिल्ली। चिकित्सा और शैक्षिक पुस्तकों पर जीएसटी लगाए जाने से छात्रों और शिक्षार्थियों पर पड़ रहे अतिरिक्त वित्तीय बोझ का मुद्दा लोकसभा में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रमुखता से उठाया। प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए इस सवाल के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सरकार का पक्ष स्पष्ट किया।

हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने प्रश्न में कहा कि चिकित्सा और शिक्षा से जुड़ी पुस्तकों पर जीएसटी लगाए जाने से विद्यार्थियों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने जानना चाहा कि क्या केंद्र सरकार ऐसी पुस्तकों को जीएसटी से पूरी तरह छूट देने अथवा न्यूनतम जीएसटी स्लैब में रखने पर विचार कर रही है, ताकि छात्रों को राहत मिल सके।

इस पर लिखित उत्तर देते हुए वित्त राज्य

मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि जीएसटी की दरें और कर छूटें जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तय की जाती हैं। जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है, जिसमें केंद्र सरकार के साथ-साथ सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। परिषद की अनुशंसाओं के अनुसार ही जीएसटी से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं।

वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान व्यवस्था के तहत मुद्रित पुस्तकें, जिनमें ब्रेल पुस्तकें भी सम्मिलित हैं, पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और ज्ञान के प्रसार को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों को कर मुक्त रखा गया है, ताकि आम नागरिकों और विद्यार्थियों को इसका सीधा लाभ मिल सके।

सरकार के इस उत्तर के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल चिकित्सा और शैक्षिक विषयों से संबंधित मुद्रित पुस्तकों पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जा रहा है और वे कर-मुक्त श्रेणी में ही बनी हुई हैं।

पाकिस्तान का यू-टर्न, भारत के साथ खेलेगा टी-20 वर्ल्ड कप मैच; बैकफुट पर शहबाज सरकार

लाहौर। पाकिस्तान सरकार ने टी-20 विश्व कप में भारत के खिलाफ होने वाले मैच के बहिष्कार का अपना फैसला वापिस ले लिया है। सरकार के एक शीर्ष सूत्र ने पीटीआई को यह जानकारी दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को श्रीलंका और बांग्लादेश ने इसके लिए तैयार किया। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच कोलंबो में 15 फरवरी को होना है। सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को श्रीलंका और बांग्लादेश से फोन आया था और उन्होंने बहिष्कार का फैसला वापिस लेने का उनका अनुरोध मान लिया है।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख अमीनुल इस्लाम ने इससे पहले एक बयान जारी करके खेल के भले के लिये पाकिस्तान से यह मैच खेलने का अनुरोध किया था । इसके बाद ही स्पष्ट हो गया था कि पाकिस्तान यह मैच खेलने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी ने इससे पहले कहा था कि मामले पर औपचारिक फैसला अगले 24 घंटे में लिया जाएगा।

अमीनुल इस्लाम के साथ आईसीसी से बातचीत को स्वीकार करते हुए यहां एक प्रेस कांफ्रेंस में नकवी ने कहा कि पीसीबी

आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कुछ मसलों पर जवाब का इंतजार कर रहा है। भारत के खिलाफ मैच 15 फरवरी को कोलंबो में होना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को श्रीलंका से राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके का भी फोन आया है जिन्होंने बहिष्कार का फैसला वापिस लेने का आग्रह किया है। जियो न्यूज ने कहा कि शरीफ ने आश्वासन दिया है कि पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ खेलेगी। नकवी ने हालांकि पत्रकारों से कहाकि हमने उनसे बात की है। मेरे लिए अभी कोई टिप्पणी करना सही नहीं होगा। हमें उनका जवाब मिल जाने के बाद हम फैसला करेंगे। हम आईसीसी का जवाब मिलने के बाद प्रधानमंत्री (शाहबाज शरीफ) के पास सलाह के लिये फिर जाएंगे। उन्होंने कहाकि कल या परसों घोषणा की जा सकती है।

स्थल पर उपस्थित अनाधिकृत निर्माणकर्ता को निर्देश दिए गए कि स्थल पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए आगे निर्माण कार्य ना किया जाए

जनसुनवाई आयी 60 समस्याएं, 31 समस्याओं का डीएम ने मौके पर ही कराया निस्तारण

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जनपदवासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 60 शिकायतें दर्ज कराई गई, जिसमें से 31 समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया।

जनसुनवाई कार्यक्रम में राजस्व, भूमि,विवाद,विद्युत,राशन अतिक्रमण ,पेयजल आदि से संबंधित समस्या दर्ज कराई गई। जनसुनवाई कार्यक्रम में साधना पुत्री दिलीप इंद्र ने अपने जन्म प्रमाण पत्र में नाम गलत चढ़ जाने की शिकायत करते हुए उसे ठीक कराए जाने की मांग की। नरेंद्र अरोड़ा, निवासी ग्राम अमीरपुर तहसील रुड़की ने ग्राम के आसपास के किसानों द्वारा सरकारी सेक्टर मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराने एवं उक्त मार्ग पर सड़क निर्माण कराए जाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया। देवराज ने ग्राम पचायत मूलदासपुर माजरा का आने जाने का रास्ता और पेयजल को नेशनल हाईवे ने बंद कर दिया है, जिसको खुलवाने को प्रार्थना पत्र दिया गया। ब्रह्मपुरी रावली महदूद के निवासियों ने गांव में लग रहे मोबाइल टावर को तत्काल रोक जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया।

राजकुमार पुत्र स्वर्गीय फूल सिंह ग्राम आन्नेकी हेतमपुर ने ग्राम आन्नेकी कलां में चक रोड पक्की बनाने एवं नालियों में बहाने वाले गंदे पानी के निस्तारण के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। आजाद सिंह पुत्र स्वर्गीय सतीश कुमार ने अपनी योगिता के अनुसार हरिद्वार सिडकुल स्थित किसी भी कंपनी में नौकरी दिलवाये जाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया। शिकायतकर्ता रवि कुमार पुत्र छोटेलाल ने मोहल्ला तेलियांन वार्ड नबर 36 में नाली एवं सड़क में हो रहे अतिक्रमण को हटाकर सड़क के दोनों ओर नाली के निर्माण हेतु प्रार्थना पत्र दिया। शिकायतकर्ता निवासी ड्रीम सिटी एवं पिंक सिटी निकट रानीपुर झाल ने रानीपुर झाल स्थित बरसाती नदी निकट ड्रीम सिटी एवं पिक सिटी कॉलोनी पर रपटा या पुल बनवाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया। शिकायतकर्ता रिंकू निवासी भारापुर ने अपनी जमीन फिरोजपुर कोर कॉलेज के पास स्थित है,जिसका खसरा नंबर 65.66 है, उक्त भूमि कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, कब उक्त भूमि से कब्जा हटाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनसुनवाई में जनता द्वारा जो भी समस्याएं दर्ज कराई जा रही है उन समस्याओं को त्वरित एवं समयबद्धता के साथ निराकरण करना सुनिश्चित करे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही एवं शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए, शिथिलता बरती जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक करवाई सुनिश्चित की जाएगी।उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि जिन शिकायतों पर स्थलीय निरीक्षण किया जाना है संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय के साथ स्थलीय निरीक्षण कर समस्या का समाधान करना सुनाश्चित करे। उन्होंने सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि कोई भी शिकायतकर्ता व्यक्ति अपनी शिकायत को दुबारा जन सुनवाई में लेकर न पहुंचे,यदि कोई व्यक्ति अपनी शिकायत को लेकर दुबारा जन सुनवाई में आता है तथा शिकायत संबंधित अधिकारी द्वारा निस्तारित की जा सकती थी एवं समय पर शिकायत का निस्तारण नहीं किया गया तो ऐसे अधिकारियों की विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा

बैठक में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज समस्याओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सीएम हेल्प लाइन में जो भी शिकायते दर्ज की जा रही है,उनको सभी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ निरंकरण करना सुनिश्चित करे,उन्होंने निर्देश दिए है कि 36 दिन से अधिक जो भी शिकायते लंबित है उनका निराकरण तत्परता से करना सुनिश्चित करे। जिसमें एल 1 पर 432 शिकायतें तथा एल 2 पर 85 शिकायतें निस्तारण हेतु लंबित है,जिन्हें शीघ्र निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए साथ ही शिकायतकर्ता से सिस्टम के माध्यम से फोन पर वार्ता करे।

ये अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, मुख्य चिकित्साधिकारी आर के सिंह, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, उप जिला अधिकारी जितेंद्र कुमार, मुख्य वित्त अधिकारी अजय कुमार, जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल, प्रोजेक्ट मैनेजर पेयजल निगम (गंगा) मीनाक्षी मित्तल, जिला अर्थ संख्या आधिकारी नलिनी ध्यानी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत, उप प्रभागीय अधिकारी पूनम कैथूरा, परियोजना निदेशक उरेडा वाई एस बिष्ट सहित जिला स्तरीय सम्बन्धित अधिकारी एवं विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादी मौजूद रहे।

एक नजर

चेकिंग के कोतवाली रुड़की पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ पकड़ा

पथ प्रवाह, हरिद्वार। कोतवाली रुड़की पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तासर किया है। पुलिस के मुताबिक रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने सोनाली पुल तिराहा के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका। पुलिस ने बताया कि पूछताछ व तलाशी के दौरान उक्त व्यक्ति के कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा व 01 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी के विरुद्ध कोतवाली रुड़की पर आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी का नाम आबिद पुत्र यामीन निवासी ग्राम रासना, थाना रोहटा, जिला मेरठ है। पुलिस टीम में अ0उ0नि0 नरेन्द्र राठी, हे0का0 यूनूस बेग, का0 राजेश देवरानी और का0 प्रदीप डंगवाल शामिल रहे।

भगवानपुर पुलिस ने 3 गोवंशीय पशुओं को कटान से पूर्व जिंदा बचाया

पथ प्रवाह, हरिद्वार। भगवानपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीन गोवंशीय पशुओं को कटान से पूर्व जिंदा बचाने का कार्य किया है। मौके से एक शातिर तस्कर गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ गोवंश संरक्षण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम में अभियोग पंजीकृत? किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा गोवंश तस्करी एवं गोकशी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुपालन में बीती 8 फरवरी को मुखबिर खास से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिकरौडा में गोवंशीय पशुओं को क्रूरता पूर्वक खींचकर कटान हेतु ले जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम सिकरौडा में दबिश दी गई, जहां से 3 गोवंशीय पशुओं को कटान से पूर्व ही जिंदा बचाया गया। मौके से आजम पुत्र सउद, निवासी ग्राम सिकरौडा, कोतवाली भगवानपुर, जनपद हरिद्वार को गोवंश संरक्षण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत हिरासत में लिया गया। कुछ तस्कर मौक़े से फ़रार होने में सफल रहे जिनकी तलाश हेतु पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस टीम में उ0नि0 मुकेश नौटियाल, अ0उ0नि0 प्रदीप चौहान, का0 अजय चंदेल शामिल रहे।

रानीपुर पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 2 व्यक्तियों को पकड़ा

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

कोतवाली रानीपुर क्षेत्रांतर्गत सुमननगर तिराहा पर लड़ाई-झगड़े की सूचना प्राप्त होने पर चौकी प्रभारी सुमननगर उ0नि0 अर्जुन कुमार मय पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर पूछताछ करने पर पाया गया कि दो व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर आपस में लड़ाई-झगड़ा कर रहे थे। जिससे मौके पर काफी भीड़ एकत्र हो गई। पुलिस द्वारा दोनों व्यक्तियों को समझाने का प्रयास किया गया, परंतु दोनों व्यक्ति उत्तेजित होकर हुड़दंग, गाली-गलौच व मारपीट पर उतारू हो गए। शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस द्वारा दोनों व्यक्तियों को धारा 170 बीएनएसएस के अंतर्गत हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आरोपितों का नाम समीर पुत्र वसीम, निवासी सलेमपुर, कोतवाली रानीपुर, जनपद हरिद्वार (उम्र 19 वर्ष) और जुल्फकार पुत्र कुरबान अली, निवासी जमील प्रधान के पास, ग्राम सलेमपुर, कोतवाली रानीपुर, जनपद हरिद्वार (उम्र 38 वर्ष) बताया गया है। पुलिस टीम में उ0नि0 अर्जुन कुमार, चौकी प्रभारी सुमननगर, कोतवाली रानीपुर, का0नि0 महेन्द्र तोमर और का0नि0 जयदेव शामिल है।

उत्तर प्रदेश अब 'बीमारू' नहीं, आर्थिक रूप से सशक्त राज्यः योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधानमंडल के बजट सत्र के मौके पर कहा कि जनसंख्या घनत्व के मामले में अव्वल यह राज्य अब 'बीमारू' नहीं बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त राज्यों की श्रेणी में आता है जो गर्व की बात है।

योगी ने सत्र की शुरुआत से पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नया आयाम दिया है और लंबे समय तक 'बीमारू राज्य अब देश में सशक्त राज्य के रुप में अपनी पहचान बना चुका है। सदन के नेता ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुये कहा कि संसदीय परंपराओं के अनुरूप बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी और इसके बाद सदन में सामान्य बजट पर चर्चा की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट सत्र के दो प्रमुख एजेंडा होते हैं। पहला राज्यपाल का अभिभाषण और दूसरा सामान्य बजट। राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों और भावी कार्ययोजनाओं का दस्तावेज होता है, जिसके माध्यम से प्रदेश की जनता को संबोधित किया जाता है। इस पर सदन में माननीय सदस्य विस्तृत चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि 11 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का सामान्य बजट प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर विचार-विमर्श किया जाएगा। बजट सत्र की कार्यवाही 20 फरवरी तक चलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आज पहली बार सदन में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नया आयाम दिया है और लंबे समय तक 'बीमारू राज्य' कही जाने वाली छवि को बदला है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश ने आर्थिक क्षेत्र में ब्रेक थ्रू किया है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और रोजगार के अवसर लगातार बढ़े हैं। पिछले पांच वर्षों से उत्तर प्रदेश एक सरप्लस बजट वाला राज्य बना हुआ है।

मुख्यमंत्री ने विधानमंडल को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ बताते हुए कहा कि लोकतंत्र संवाद से चलता है, न कि कार्यवाही को बाधित करके। सरकार हर सकारात्मक सुझाव को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तत्पर है, लेकिन सदन की कार्यवाही में व्यवधान नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश विधानसभा में कई नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, जो स्वस्थ संसदीय परंपराओं का प्रमाण हैं।

मेला ड्यूटी में लगे अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वाहन संवेदनशीलता के साथ करें: जिलाधिकारी मयूर दीक्षित

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

शारदीय कांवड़ यात्रा को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला सभागार में जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट के अलावा संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि शारदीय कांवड़ यात्रा एवं शिवरात्रि के दौरान जनपद में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, ऐसे में यातायात व्यवस्था, सुरक्षा,स्वच्छता,स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, विद्युत आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन की समुचित तैयारियों को लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कांवड़ मार्ग,राष्ट्रीय राज मार्ग पर लाइट,पेयजल एवं शौचालयों की व्यवस्था के साथ ही पर्याप्त

पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने पुलिस अधिकारियों से यातायात डायवर्जन प्लान तैयार करने, संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने एवं अफवाहों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को एंबुलेंस, चिकित्सक दल एवं प्राथमिक उपचार केंद्रों में सभी चिकित्सा सुविधा सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए गए। नगर निगम, सिंचाई विभाग एवं जिला पंचायत को स्नान घाटों एवं कांवड़ मार्गों पर नियमित सफाई, कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही नगर निगम को मोबाइल टायलेट की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जल संस्थान एवं विद्युत विभाग को निर्बाध पेयजल व बिजली आपूर्ति बनाए रखने को कहा गया। उन्होंने सभी जोनल मजिस्ट्रेट एवं पुलिस के अधिकारी को आज ही मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने एनएचएआई के अधिकारियों को नजीबाबाद राष्ट्रीय मार्ग पर पड़े मलबे को तत्काल हटाने के निर्देश दिए ताकि मार्ग कही पर भी अवरुद्ध न हो, जिससे कि कोई दुर्घटना आदि की संभावना बन जाए। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारी को गंगा घाटों एवं समस्त पुलों पर किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को कांवड़ यात्रा में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को निर्धारित रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से चस्पा करने और ओवररेटिंग न करने के सख्त निर्देश दिए हैं साथ ही भोजन की गुणवत्ता, एक्सपायरी सामग्री की जांच और नियमित निरीक्षण कर खराब खाना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपर रोड पर जो निर्माण कार्य गतिमान है कांवड़ यात्रा के समय कार्य को रोक दिया जाए तथा उक्त मार्ग को दूरस्त करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर के सिंह, सीओ ट्रैफिक बिपेंदर सिंह, सीओ एसडीआरएफ सुशील रावत, ट्रैफिक इंचार्ज हितेश कुमार, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, अधीक्षण अभियंता लोनिवि डीके सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर पेयजल निगम (गंगा) मीनाक्षी मित्तल, सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

एक नजर

जगजीतपुर से लापता युवक का नहीं लगा सुराग

पथ प्रवाह, हरिद्वार। कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर से लापता युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस ने युवक की गुमशुदगी को अब मुकदमें में दर्ज कर अपनी जांच तेज कर दी है। पुलिस के मुताबिक श्याम सिंह निवासी विकास कॉलोनी जगजीतपुर ने बताया कि उनका पुत्र विवेक सिंह (39) उर्फ हैप्पी 16 जनवरी को कहीं चला गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने रिश्तेदारी और संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की, मगर कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। इस मामले में 20 जनवरी को गुमशुदगी दर्ज की गई थी। अब तक कोई सुराग न मिलने पर पुलिस ने गुमशुदगी को मुकदमे में तरमीम कर लिया है।

व्यापारी के बंद कराए गए चालू खाते से 12 करोड़ का लेनदेन, मुकदमा दर्ज

पथ प्रवाह, हरिद्वार। कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में एक व्यापारी द्वारा अपने बंद कराए गए चालू खाते से 12 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेनदेन होने का पता चलने पर होश उड़ गए। जानकारी सामने आने पर पीड़ित ने बैंक कर्मचारी पर धोखाधड़ी और धमकाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाया है। कोर्ट के आदेश पर ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक अवनीत अरोड़ा ने शिकायत में बताया कि उन्होंने ज्वालापुर रोड स्थित बंधन बैंक की शाखा में अपनी दुकान का चालू खाता खुलवाया था, जिसे अप्रैल 2025 में बंद कराने के लिए कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर आशु कुमार को लिखित आवेदन के साथ एटीएम कार्ड और चेकबुक सौंपी थी। इसके बाद उन्हें बैंक खाता बंद होने की पुष्टि की गई। लेकिन, 13 अगस्त 2025 को कोरियर से मिली बैंक स्टेटमेंट को देखकर उन्हें पता चला कि 1 मई से 26 जून 2025 के बीच इस खाते में करीब 12.14 करोड़ रुपये जमा हुए और 12.12 करोड़ निकाले गए। पीड़ित का कहना है कि उस अवधि में उन्होंने कोई लेनदेन नहीं किया। आरोप है कि बैंक रिकॉर्ड में खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भी बदली गई। आरोप है कि 20 अगस्त 2025 को जब वह बैंक पहुंचे तो कर्मचारी ने न तो सही तरीके से बात की, बल्कि कार्रवाई पर अंजाम भुगतने की धमकी दी।

कार से स्टंट करना पड़ा भारी, पुलिस ने काटा चालान

पथ प्रवाह, हरिद्वार। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर एक कार द्वारा किए गए खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार का पता लगाकर चालान की कार्रवाई की। कार चला रहे युवक ने इस संबंध में माफी मांगी ओर भविष्य में ऐसा फिर न करने की बात कही। हरिद्वार पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की। पुलिस द्वारा कार मालिक से संपर्क किया गया, जिस पर उसने अपने कृत्य को भूल स्वीकार करते हुए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह स्वयं पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर चालान कटवाया। कार चालक ने भविष्य में इस प्रकार का कोई भी स्टंट न करने का पुलिस को वचन दिया। हरिद्वार पुलिस ने अपील करते हुए कहा कि स्टंट नहीं, सुरक्षित ड्राइविंग करें। क़ानून का पालन करें, अपनी और दूसरों की जान की सुरक्षा करें।

कीटनाशक छिड़काव के दौरान किसान की मौत

पथ प्रवाह, हरिद्वार। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हरचन्दपुर में कीटनाशक के छिडकाव के दौरान एक किसान की मौत हो गई। मृतक का नाम टीकाराम पुत्र राम सिंह, निवासी ग्राम हरचन्दपुर, कोतवाली लक्सर, जनपद हरिद्वार बताया गया है। पुलिस के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि टीकाराम अपने खेत में सरसों की फसल पर कीटनाशक का छिडकाव कर रहे थे। इसी दौरान कीटनाशक की तीव्र गंध उनके मुंह में चली गई, जिससे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। हालत गंभीर होने पर परिजन उन्हें तत्काल उपचार के लिए भूमानन्द हॉस्पिटल, हरिद्वार ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा मृतक के पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। मामले से संबंधित आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से किसानों को कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग को लेकर जागरूक करने की मांग की है।

हरजोली झोझा में दर्जाधारी देशराज कर्णवाल ने किया सड़क का उदघाटन

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के अकबरपुर झोझा गांव में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल द्वारा इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस सड़क के निर्माण से जहाँ ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी वहीं अरबी मदरसे की छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा।

इस इंटरलौकिंग सड़क का उदघाटन करने से पहले राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल का सैंकड़ो ग्रामीणों द्वारा पगड़ी पहनाकर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान देशराज कर्णवाल ने कहा कि उत्तराखंड सरकार लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहर से लेकर गांव गांव के विकास को लेकर बेहद गंभीर है। गौरतलब है कि पिछले दिनों कीचड़ होने के चलते अरबी मदरसे में जाने

वाले बच्चों को इस मार्ग से गुजरने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जिसके चलते देशराज कर्णवाल ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही सड़क का निर्माण कराया जाएगा। आज लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़क का उनके द्वारा उद्घाटन कराया गया। इस दौरान ग्रामीणों में भारी उत्साह था। इस मौके पर कारी मेहताब, कारी मुराद भट्टू, प्रधान इकराम प्रधान, तालिब, जमशेद, रहमान, जाबिर, हाजी जमशेद, हाजी रियासत, डॉक्टर गय्यूर आदि सैंकड़ो ग्रामीण मौजूद रहे।

घोसीपुरा मारपीट प्रकरण में एक और आरोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। कोतवाली मंगलौर के ग्राम घोसीपुरा में बीती 6 फरवरी को झगड़ा व मारपीट आदि के संबंध में वादी अमजद निवासी घोसीपुरा द्वारा थाना कोतवाली मंगलौर पर हत्या का प्रयास सहित आदि अनेक धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। प्रकरण में घायल कुछ व्यक्तियों को पुलिस द्वारा सरकारी वाहन से उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे घटनाक्रम से संबंधित वीडियो के बीच एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने आरोपित पक्ष के लोगों के चिन्हिकरण व तलाश के प्रयास शुरु करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार किया।

आरोपी का नाम नूर हसन पुत्र हनीफ निवासी घोसीपुरा कोतवाली मंगलौर जनपद हरिद्वार है। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक वीरपाल सिंह, उप निरीक्षक राम बहादुर, कांस्टेबल किशन देव राणा और कांस्टेबल मोहम्मद आमिर शामिल है।

आम के 44 पुराने पेड़ों को कटवाकर लगाए 100 से अधिक नए फलदार पौधे

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

ग्राम जियापोता में उद्यान विभाग की अनुमति के बाद काटे गए पुराने आम के पेड़ों के बदले अब बाग में नए फलदार पौधों का रोपण किया जा रहा है। विभागीय शर्तों के अनुसार प्रत्येक कटे एक पेड़ के बदले दो नए पौधे लगाए जाने थे। इसी क्रम में बाग स्वामियों की ओर से अब तक 100 से अधिक फलदार पौधे रोपित किए जा चुके हैं। इस पहल को पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

बाग स्वामी इंदर मोहन ने बताया कि पिछले कई वर्षों से आम की फसल लगातार खराब हो रही थी। उत्पादन में गिरावट के साथ-साथ पेड़ों में कीट और रोग का प्रकोप बढ़ गया था, जिससे हर साल भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। ऐसे में उद्यान विभाग से विधिवत अनुमति लेकर पुराने और रोगग्रस्त आम के पेड़ों को हटाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि अब बाग में अमरूद, नींबू और मौसमी जैसी उन्नत किस्मों के फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं, जो भविष्य में बेहतर उत्पादन और स्थायी आय का साधन बनेंगे। बाग स्वामी कौशल किशोर और चेतना भसीन ने बताया कि तीनों भाइयों ने संयुक्त रूप से कुल 44

आम के पेड़ों को काटने की अनुमति प्राप्त की गई थी। विभागीय नियमों और शर्तों का पूरी तरह पालन करते हुए ही कटाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई और अब उससे कहीं अधिक संख्या में नए पौधे रोपित किए जा रहे हैं। किसान इसरार ने बताया कि मौके पर मौजूद अधिकांश आम के पेड़ धीरे-धीरे खराब हो चुके थे। पेड़ों में कीड़े लगने से फसल प्रभावित हो रही थी और हर साल नुकसान झेलना पड़ रहा था। इसी कारण उद्यान विभाग से अनुमति लेकर नई फसलों की ओर रुख किया गया है।

संपादकीय

उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ता सियासी तापमान

उत्तराखंड में भले ही विधानसभा चुनाव 2027 में होने हों, लेकिन राज्य की राजनीति में अभी से गर्माहट साफ दिखाई देने लगी है। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। जनसभाओं, संगठनात्मक बैठकों और मुद्दा आधारित आंदोलनों के जरिए दोनों दल अपने-अपने पक्ष को मजबूत करने में जुट गए हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 2027 की चुनावी बिसात अब बिछनी शुरू हो गई है।

भाजपा सरकार अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने प्रमुखता से रख रही है। समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण पर कार्रवाई, चारधाम ऑल वेदर रोड, कुम्भ मेला-2027 की तैयारियां और बुनियादी ढांचे का विस्तार सरकार के प्रमुख एजेंडे में शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को भाजपा चुनावी ताकत के रूप में प्रस्तुत कर रही है। पार्टी का प्रयास है कि 'स्थिर सरकार और निर्णायक नेतृत्व' के संदेश को घर-घर तक पहुंचाया जाए।

वहीं कांग्रेस सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और पर्वतीय क्षेत्रों की उपेक्षा जैसे मुद्दों पर घेरने की रणनीति अपना रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि विकास का दावा ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर है और सरकार केवल प्रचार तक सीमित रह गई है। पार्टी संगठन को नए सिरे से खड़ा करने और पुराने नेताओं को सक्रिय करने की कोशिशों में जुटी है, हालांकि आंतरिक गुटबाजी कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।

राज्य में सियासी तापमान बढ़ने की एक बड़ी वजह स्थानीय मुद्दे भी हैं। नगर निकायों, पंचायतों और सहकारी संस्थाओं के चुनावों ने राजनीतिक दलों को जमीनी स्तर पर सक्रिय कर दिया है। हरिद्वार, देहरादून और ऊधमसिंह नगर जैसे शहरी क्षेत्रों में विकास, जबकि पर्वतीय जिलों में रोजगार और पलायन प्रमुख चुनावी मुद्दे बनते दिख रहे हैं।

इसके अलावा, क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय नेताओं की संभावित सक्रियता भी राजनीतिक समीकरणों को रोचक बना सकती है। युवा मतदाता, महिलाओं की भागीदारी और सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव 2027 के चुनाव को पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण और प्रतिस्पर्धी बना देगा।

कुल मिलाकर, उत्तराखंड में 2027 का विधानसभा चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि यह विकास, पहचान और भरोसे की राजनीति का भी निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। आने वाले महीनों में सियासी पारा और चढ़ना तय है।

लोकतंत्र के सर्वोच्च आसन पर उठते सवाल

सनत जैन

लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। यह वह आसन है, जो सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान एवं जिम्मेदारी का प्रतीक है। संविधान में परिभाषित है। लोकसभा का अध्यक्ष और राज्य सभा का सभापति पार्टीगत राजनीति से ऊपर उठकर सदन का संचालन करेगा। दोनों ही सदन में सभी सदस्यों के हितों के संरक्षण की जिम्मेदारी अध्यक्ष और सभापति की होती है। हालिया घटनाक्रम ने इसी धारणा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी करना कोई साधारण राजनीतिक घटना नहीं है। संसदीय लोकतंत्र की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है। पिछले कई सत्रों से लोकसभा में विपक्ष आरोप लगाता रहा है, उन्हें सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा। बोलने के पहले तरह-तरह से उन्हें रोका जा रहा है। सदन के अंदर सदस्यों को बोलने की जो स्वतंत्रता थी, उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाधित किया जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जैसे संवैधानिक और परंपरागत अवसर पर भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने की अनुमति न मिलना वहीं सत्ता पक्ष के एक सदस्य को बोलने का अवसर दिया गया। इसने असंतोष को आर और पार की लड़ाई में लाकर खड़ा कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष को खुली छूट दी जाती है। जबकि विपक्ष को सवालों ओर नियमों का हवाला देकर बोलने नहीं दिया जाता है। विपक्ष यह कहने से नहीं चूक रहा है, कि आसंदी द्वारा सत्ता पक्ष के लिए अलग, विपक्ष के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष का यह तर्क कि 'सदन नियम और परंपरा से चलेगा' अपने आप में सही है, लेकिन सवाल यह है, कि क्या ये नियम सबके लिए समान रूप से लागू हो रहे हैं? पिछले 10 वर्षों में विपक्ष द्वारा जब भी कोई स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष को दिया गया, किसी को मंजूरी नहीं दी गई। जबकि परंपराएं और लोकसभा की कार्यवाही में ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जहां पर विपक्ष को स्थगन प्रस्ताव में बोलने का अवसर दिया गया। जब सत्ता पक्ष कांग्रेस को 'गद्दार' कहता है, तब वह सदन की मर्यादा है? और जब विपक्ष उसका जवाब देना चाहता है, तब उसे 'आउट ऑफ प्रोसीडिंग' बताकर रोक दिया जाता है। तो यह किस तरह की निष्पक्षता है? विपक्ष का आरोप है कि अध्यक्ष का व्यवहार निष्पक्ष एवं मध्यस्थता वाला नहीं है। ऐसा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आसंदी का व्यवहार सत्ता पक्ष के रक्षक का है। पिछले वर्षों में जिस तरह से बिल और कानूनों को बिना किसी चर्चा के हो हल्ले में पास कर दिया गया। यही कारण है कि विपक्ष ने अब अविश्वास प्रस्ताव जैसा असाधारण कदम उठाने का मन बनाया है। पिछले 76 सालों में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तीन बार लाया गया है। चौथी बार ऐसी स्थिति बनना अपने आप में असाधारण और चिंताजनक है।

संविधान के अनुसार, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ लिखित नोटिस आवश्यक होता है। यह प्रस्ताव तभी लाया जाता है जब विपक्ष यह मान ले कि अध्यक्ष सदन की निष्पक्षता बनाए रखने में असफल हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर एकमत हैं। महिला सांसदों ने भी लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपनी नाराजी जताई है। जो यह दर्शाता है, असंतोष केवल एक दल अथवा एक वर्ग तक सीमित नहीं है। इस पूरे विवाद का सबसे गंभीर पहलू यह है, पिछले कई वर्षों में सदन के सत्र छोटे होते जा रहे हैं। संसद की कार्यवाही बार-बार ठप्प होना अब सामान्य हो गया है। इसका लाभ उठा कर सत्ता पक्ष बिल पास कर लेती है। बजट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के बजाय बार-बार कार्यवाही स्थगित होना, अध्यक्ष द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया जाता है। जबकि नियमों के अनुसार विपक्ष की आवाज को अध्यक्ष का संरक्षण मिलना चाहिए। आसंदी की इस कार्रवाई से लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर करता है। इतिहास गवाह है, जब-जब अध्यक्ष ने निष्पक्षता दिखाई, तब-तब विपक्ष ने भी मर्यादा का पालन किया है। जब कुर्सी की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, तब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराव बढ़ता है। वर्तमान में स्थिति यहां तक पहुंच गई है, अध्यक्ष का आसन राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है।

उप्र में बेमौसम राजनीतिक... भगवा बनाम भगवा और संत बनाम संत का कैसे होगा अंत

ऋतुपर्ण दवे

यह सच है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता ज्यादातर उत्तरप्रदेश से ही होकर निकलता है। यह भी सच है कि भले ही देश में नरेन्द्र मोदी को लेकर कोई विकल्प न हो लेकिन उनके उत्तराधिकारी के रूप में अघोषित रूप से योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले आता है। वहीं अक्सर सियासत में कहे.अनकहे ऐसे दांव.पेंच चले जाते हैं या हो जाते हैं जिससे आसान राहें भी मुश्किलें बढ़ाती नजर आने लगती हैं। फिलाहाल उत्तरप्रदेश में चुनावी सरगर्मी तो नहीं है लेकिन राजनीतिक सरगर्मी ने पहले पौष की कड़कड़ती ठण्ड और अब माघ की जाती ठण्ड में भी जबरदस्त और इतनी कि लू सरीखे सियासी तपन का अहसास जरूर करा दिया।

दरअसलए उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के प्रमुख स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का 28 जनवरी को माघ मेला में स्नान किए बिना लौटना भले ही एक धार्मिक मामला हो। लेकिन वास्तव में सियासी ज्यादा रहा। नए वर्ष की शुरुआत में ही उत्तरप्रदेश में श्भगवा बनाम भगवाश् का मुद्दा जबरदस्त राजनीतिक और धार्मिक विमर्श का अहम मुद्दा रहा। लेकिन इसका यह आशय नहीं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान और पालकी सहित जाने की जिद और प्रशासन के नहीं जाने देने से उत्पन्न विवाद इतना बड़ा तूल पकड़ेगाए इसका जनमानस को जरूर अंदाजा नहीं रहा। हाँए सियासतदारों को जरूर बैठेए बिठाए बड़ा मौका मिल गया।

वास्तव में अविमुक्तेश्वरानंद अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वो किसी को भी नहीं छोड़ते ऐसी स्थिति में उनसे इस टकराहट को असाधारण माना जा रहा है। यदि वास्तव में प्रयागराज मेला प्रशासन चाहता तो इसे टाल सकता था लेकिन कहते हैं न कि राजनीति में लिए गए छोटे से छोटे फैसलों के दूरगामी परिणाम मतलब भरे होते हैं। हुआ भी वही। अब लोग भले ही यह कहें कि सरकार ने गलत किया या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने। लेकिन सच तो यह है कि इसे प्रशासन की चूक या भूल भी कहना बेमानी होगा। एक ओर रूठे हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी ने शंकराचार्य विवाद के दौरान ही सीधे नाम न लेकरए सनातन धर्म की आड़ में राष्ट्रविरोधी या सनातन विरोधी एजेंडा चलाने वालों को श्कालनेमिश् कह दिया। जाहिर है इशारा अविमुक्तेश्वरानंद पर था। बाद में प्रयागराज में जो घटाए उसे देश ने देखा। बात असली और नकली शंकराचार्य तक जा पहुंची तो भला अविमुक्तेश्वरानंद कैसे चुप रहतेघ् उन्होंने भी सीधे.सीधे आदित्यनाथ से टकराने की रणनीति अपना ली। इस बीच प्रशासन ने शंकराचार्य को नोटिस पकड़ा दिया कि 18 जनवरी को त्रिवेणी संगम में जबरदस्ती घुसने के प्रयास से भगदड़ मच सकती थी। इतना ही नहीं यह तक पूछ लिया कि क्यों न उन्हें भविष्य के मेलों में भाग लेने से रोक दिया जाएघ् तल्खी और तब बढ़ी जब अगले नोटिस में मेला अधिकारियों ने 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए शंकराचार्य की उपाधि पर ही सवाल उठाए विवाद को गहरा दिया। ऐसा देश ने पहली बार देखा।

शह.मात के इस खेल में स्वामी अविमुक्तेश्वरनद ने अपने जवाब में उल्टा पूछ लिया कि ष्ना प्रशासनए ना उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्रीए और ना ही देश के राष्ट्रपति तय करेंगे कि कौन शंकराचार्य होघ् हालांकि शंकराचार्य पर आरोप लगे कि वो कांग्रेसी विचारधारा के हैं। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन किया और कई बड़े नेताओं ने मुलाकात की। निश्चित रूप से वक्त के साथ शंकराचार्य विवाद राजनीतिक रूप ले चुका था। जिसमें कई मोड़ आए। एक ओर जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी विश्वास व्यक्त किया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज और उत्तरप्रदेश सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकलेगा वहीं प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनसे स्नान करने की अपील की और कहा कि मैं ज्योतिष्पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में प्रणाम करता हूंए उनसे प्रार्थना है कि वह स्नान कर इस विषय का समापन करें। लेकिन यह हो न सका। बस यहीं से जो मामला भगवा बनाम भगवा था उसे पार्टी लाइन की ओर भी समझा जाने लगा। उत्तरप्रदेश में भाजपा की गुटबाजी जगजाहिर है। यह तब और समझ में आई जब बीते महीने 30 जनवरी को महोबा विधायक में भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत और योगी कैबिनेट के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आपस में तकरार हो गई। मंत्री एक कार्यक्रम से लौट रहे थे कि दोपहर करीब साढ़े तीन बजे विधायक ने 100 ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर उनका रास्ता रोक लिया और 100 गांवों में पानी न पहुंचने और पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होने पर नाराजगी जताई। इसी तरह केशव प्रसाद मौर्य का बयान आना कोई सामान्य घटना नहीं है। बहरहाल इस पर भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई लेकिन मौर्य का निवेदन हाईकमान का रुख माना जा रहा है तो ज़िला प्रशासन का ऐक्शन योगी सरकार का कदम। यकीनन ऐसी घटनाओं के पीछे बड़ी सियासत होगी जो आम लोगों की समझ से बाहर है। वैसे सबको पता है कि कैसी कवायद से योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद उनकी कार्यप्रणाली से उनका कद लगातार बड़ा होता चला गया।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 28 जनवरी को दुखी मन से वाराणसी से विदा ली और बिना स्नान लौट गए। घटना को अकल्पनीय बताया। हालांकि संतों में भी दो परस्पर विरोधी गुट बन गए। वही अविमुक्तेश्वरानंद भी कमर कस के तैयार हैं। उन्होंने उत्तरप्रदेश में गाय को राजमाता का दर्जा दिलाने और गौ हत्या रोकने के लिए 40 दिनों की मोहलत दी जिस पर संत परमहंसाचार्य ने इसे राजनीति से प्रेरित बता कहा कि केवल गाय नहीं पूरा गौवंश ;बैलए बछड़ाए नंदीद्ध को राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो तभी पूर्ण गौ.रक्षा संभव है।

बहरहाल योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की इस जुबानी जंग को लोग ऊंचे दर्जे की राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में कुछ इसे केन्द्र और राज्य के बीच का मसला समझते हैं तो कुछ इसे योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद से जोड़कर देख रहे हैं। बहरहाल ऐसी घटनाओं से अपने आप ही समझ आता है कि माजरा क्या हैघ् अब देखना है कि अगले वर्ष उत्तरप्रदेश में चुनाव हैं ऐसे में भगवा बनाम भगवा और संत बनाम संत की इस लड़ाई में किसेए कितना नफा.नुकसान होता है क्योंकि इतने बड़े मसले पर भाजपा केन्द्रीय नेतृत्व या पार्टी की चुप्पी भी बड़ा इशारा जरूर करती है।

पोषण सुरक्षा और टिकाऊ कृषि का प्रभावी साधन हैं दालें

योगेश कुमार गोयल

हर साल 10 फरवरी को मनाया जाने वाला 'विश्व दलहन दिवस' हमें यह सोचने का अवसर देता है कि जिन दालों को हम रोजमर्रा के भोजन का साधारण हिस्सा मान लेते हैं, वे वास्तव में मानव सभ्यता और प्रकृति के बीच संतुलन की एक गहरी कड़ी हैं। खेतों से लेकर थाली तक की यह यात्रा केवल भोजन भर की नहीं है बल्कि इसमें पोषण, पर्यावरण, कृषि और भविष्य की खाद्य सुरक्षा के सूत्र छिपे हैं। वर्ष 2026 की आधिकारिक थीम 'विश्व की दलहनः सादगी से उत्कृष्टता की ओर' इसी सच्चाई को रेखांकित करती है कि छोटे से दिखने वाले बीज किस तरह वैश्विक समाधान बनकर उभर रहे हैं। यह दिवस खाद्य एवं कृषि संगठन के नेतृत्व में विश्वभर में मनाया जाता है। दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की घोषणा के बाद से 2019 से यह निरंतर मनाया जा रहा है। इसकी प्रेरणा 2016 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष से मिली थी, जिसने पहली बार वैश्विक मंच पर यह स्पष्ट किया कि दालें केवल पारंपरिक भोजन नहीं, पोषण सुरक्षा और टिकाऊ कृषि का प्रभावी साधन हैं।

दलहन, यानी फलीदार पौधों से प्राप्त सूखे और खाने योग्य बीज, सदियों से मानव आहार का आधार रहे हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ये भोजन की रीढ़ रहे जबकि आधुनिक समय तक कुछ क्षेत्रों में इन्हें साधारण या कम मूल्य वाला भोजन समझा गया लेकिन पोषण विज्ञान ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। आज यह स्वीकार किया जा चुका है कि दालें उच्च गुणवत्ता वाले पौध-आधारित प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत हैं। इनके साथ मिलने वाला आहार फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है और हृदय रोगों के जोखिम को कम करता है। आयरन, जिंक, फोलेट, मैग्नीशियम और बी-विटामिन्स जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व इन्हें हर आयु वर्ग के लिए उपयोगी बनाते हैं। कम वसा और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण ये आधुनिक जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती हैं।

पर्यावरण की दृष्टि से दालों का महत्व और भी व्यापक है। इनमें मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की प्राकृतिक क्षमता होती है, जिससे खेतों की उर्वरता बढ़ती है और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है। अन्य फसलों की तुलना में इन्हें कम पानी की जरूरत पड़ती है और इनका कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है। यही कारण है कि बदलते जलवायु परिदृश्य में दलहन को जलवायु-अनुकूल और भविष्य की फसल माना जा रहा है। सीमित संसाधनों और अनिश्चित मौसम के दौर में ये फसलें किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए भरोसेमंद विकल्प बनती जा रही हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भी दलहन की भूमिका निर्णायक है। तेजी से बढ़ती आबादी, कुपोषण और जलवायु अस्थिरता के बीच दालें सस्ती, सुलभ और पोषण से भरपूर समाधान प्रस्तुत करती हैं। भूखमुक्त समाज, बेहतर स्वास्थ्य और टिकाऊ विकास जैसे वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने में इनका योगदान प्रत्यक्ष और प्रभावी है। भारत में विश्व दलहन दिवस का महत्व केवल एक वैश्विक तिथि तक सीमित नहीं रहता बल्कि यह देश की कृषि परंपरा, पोषण दृष्टि और सांस्कृतिक चेतना से गहराई से जुड़ जाता है। भारत न केवल विश्व के प्रमुख दलहन उत्पादक और उपभोक्ताओं में अग्रणी है बल्कि यहां की खाद्य संस्कृति में दाल को संतुलित आहार की आत्मा माना गया है। दाल-चावल, दाल-रोटी और खिचड़ी जैसे सरल, सुलभ और पौष्टिक भोजन सदियों से भारतीय समाज में स्वास्थ्य, सादगी और सहजीवन के प्रतीक रहे हैं। दलहन केवल थाली की शोभा नहीं बल्कि पोषण सुरक्षा की मजबूत आधारशिला हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, खनिज और सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कुपोषण से लड़ने और स्वास्थ्य सुधारने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। विशेषकर शाकाहारी आबादी के लिए दालें सस्ती, टिकाऊ और भरोसेमंद प्रोटीन स्रोत हैं।

कुल मिलाकर, यह दिवस किसानों के लिए भी नई संभावनाओं का द्वार खोलता है। दलहन आधारित फसल चक्र अपनाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटती है और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। परिणामस्वरूप किसानों की लागत कम होती है और आय में स्थिरता आती है। साथ ही, जलवायु परिवर्तन के दौर में दलहन खेती पर्यावरण के अनुकूल समाधान प्रस्तुत करती है। उपभोक्ताओं के लिए यह अवसर अपने भोजन विकल्पों पर पुनर्विचार करने का संदेश देता है, अधिक पौध आधारित, स्थानीय और पोषण-संपन्न आहार की ओर लौटने का आह्वान।

डॉ. नित्यानंद का पूरा जीवन - हिमालय, प्रकृति, समाज और राष्ट्र को रहा समर्पित : मुख्यमंत्री

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दून विश्वविद्यालय, देहरादून में डॉ. नित्यानंद की जन्मशताब्दी वर्ष समारोह के उपलक्ष्य पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सत्तत हिमालयी पर्यावरण पुरस्कार 2025 -26 से जयेंद्र सिंह राणा एवं श्री संजय सत्यवली को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने डॉ. नित्यानंद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन हिमालय, प्रकृति, समाज और राष्ट्र को समर्पित किया। उनकी सोच, हिमालय की शिखरों जैसी ऊँची और उनका सेवा-भाव हिमालय की घाटियों से भी गहरा था। उनका मानना था कि हिमालय की रक्षा करना, भारतीय सभ्यता और राष्ट्र के भविष्य के लिए भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. नित्यानंद ने विज्ञान को अध्यात्म से, शोध को लोक-जीवन से और चिंतन को राष्ट्रहित से जोड़ने का कार्य किया। वो समाज के प्रत्येक वर्ग में राष्ट्रभाव और सामाजिक चेतना का संचार करते रहे। उन्होंने गांवों के सशक्तिकरण के लिए भी आजीवन कार्य किया। वे प्रतिवर्ष अपनी आय से लगभग 40 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किया करते थे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि 1991 में उत्तरकाशी और 1999 में चमोली की आपदा के बाद डॉ. नित्यानंद ने बिना किसी विलंब के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर राहत एवं पुनर्वास कार्यों का ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया, जो आज भी श्रेष्ठ माना जाता है। उन्होंने मनेरी गाँव को अपना केंद्र बनाकर वहाँ 400 से अधिक भूकंप रोधी मकानों के निर्माण का कार्य भी कराया। उन्होंने उस क्षेत्र के 50 से अधिक गाँवों को मॉडल गाँवों के रूप में विकसित करने का कार्य भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा डॉ. नित्यानंद ने 'उत्तरांचल दैवीय आपदा पीड़ित सहायता समिति' का गठन कर उन्होंने सेवा को संस्थागत स्वरूप दिया, जो आज भी देशभर में आपदाओं के समय मानवता की सेवा का सबसे बेहतर उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। उन्होंने कहा देहरादून में संचालित डॉ. नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र उनके विचारों को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम बन चुका है। यह केंद्र हिमालयी अध्ययन, सतत विकास, आपदा प्रबंधन और नीति-निर्माण के क्षेत्र में नई दिशा दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार हिमालय संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण अभियान जैसे विभिन्न माध्यम से हिमालय के दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया है। राज्य में प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम के माध्यम से अब तक हिमालयी क्षेत्र में 72 टन कार्बन उत्सर्जन को कम किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए पौधारोपण अभियान, जल संरक्षण अभियान और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों चलाए जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सौर ऊर्जा सहित अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के नौले, धारे एवं वर्षा आधारित नदियों जैसे परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण हेतु 'स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी का गठन किया है। मुख्यमंत्री ने सभी से आह्वान करते हुए कहा कि हम सभी जीवन के प्रत्येक प्रमुख अवसर पर जैसे जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ या कोई अन्य स्मरणीय दिन पर एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी नियमित देखभाल भी करें। जिससे हम सभी देवभूमि में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे पाएंगे। इस अवसर पर आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ दिनेश, आरएसएस प्रान्त प्रचारक डॉ. शैलेन्द्र, विधायक विनोद चमोली, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विधायक बृजभूषण गैरोला, डॉ. कमलेश कुमार, उत्तरांचल उत्थान परिषद के संरक्षक प्रेम बड़ाकोटी, कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, रविदेवानंद, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

एक नजर

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्मार्ट मीटर जागरूकता शिविर का विरोध

पथ प्रवाह, हरिद्वार। नया हरिद्वार स्थित हरिहर मंदिर में यूपीसीएल द्वारा स्मार्ट मीटर को लेकर लगाए गए जागरूकता शिविर का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए स्मार्ट मीटर का विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकारी अधिकारियों पर प्राइवेट कंपनी का प्रचार करने का आरोप लगाते हुए आम जनता से स्मार्ट मीटर ना लगवाने की अपील भी की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज सैनी ने कहा कि सरकार जनविरोधी फैसले ले रही है। सरकारी अधिकारी प्राइवेट कंपनी का प्रचार प्रसार कर जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर सबसे पहले जनप्रतिनिधियों के यहां लगाए जाएं। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कैश खुराना और दीपक टंडन ने कहा कि अधिकारियों को बताना चाहिए कि पुराने मीटर में क्या कमी है, जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगने से मीटर रीडर का काम कर रहे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जहां भी स्मार्ट मीटर लगे हैं। वहां लोग इससे परेशान हैं। इसलिए हरिद्वार में स्मार्ट मीटर नहीं लगने दिया जाएंगे। स्मार्ट मीटर का प्रचार प्रसार भी नहीं करने दिया जाएगा।

विरोध करने वालों में जतिन हांडा, मनोज धीमान, सोम त्यागी, रामबाबू बंसल, विकास चंद्रा सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। यूपीसीएल के एडीओ अजय धीमान का कहना है कि पुराने मीटर में सही से रीडिंग नहीं आ पाती है। जिससे उपभोक्ता और विभाग दोनों परेशान हैं। स्मार्ट मीटर पूरी तरह तरह से सुरक्षित है। इससे बिजली का सटीक बिल प्राप्त होगा और उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा।

भीमगोडा में किया जा रहा अनाधिकृत निर्माण किया सील

पथ प्रवाह, हरिद्वार। एचआरडीए ने अनाधिकृत रूप से किये जा रहे एक व्यवसायिक अवैध निर्माण को सील किया है। निर्माण सैकेंड फ्लोर पर किया जा रहा था। एचआरडीए ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सील तोड़कर काम किया तो मुकदमा दर्ज कराते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सोनिका के निर्देश पर अवैध निर्माणों को सील करने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। सचिव मनीष कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को हरिद्वार में भीमगौड़ा कुंड के निकट रेलवे लाइन के पास एक अवैध निर्माण की सूचना मिली। निर्माण नवीन व मुन्ना परांठे वाला द्वारा किया जा रहा था। यह निर्माण करीब 40 गुणा 20 फीट में पूर्व निर्मित भवन के द्वितीय तल पर किया जा रहा था। अनाधिकृत व्यवसायिक निर्माण को प्राधिकरण क़ी टीम द्वारा पुलिस बल की उपस्थिति में सील किया गया। स्थल पर उपस्थित अनाधिकृत निर्माणकर्ता को निर्देश दिए गए कि स्थल पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए आगे निर्माण कार्य ना किया जाए।

15 फरवरी तक नई योजनाओं की स्वीकृति अनिवार्य, कुम्भ–2027 के कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में सचिव समिति की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में शासन की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने को लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा सभी विभागों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए।

मुख्य सचिव ने आगामी वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित नए कार्यों को लेकर सख्त समयसीमा तय करते हुए निर्देश दिए कि 15 फरवरी तक सभी आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने समस्त कार्यों का वार्षिक कैलेंडर तैयार करे और उसी के अनुरूप योजनाओं एवं गतिविधियों का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया जाए।

कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने विशेष जोर देते हुए कहा कि यह आयोजन राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, इसलिए इससे संबंधित सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्रकार की स्वीकृतियां, प्रक्रियाएं एवं तकनीकी औपचारिकताएं समयबद्ध ढंग से पूर्ण की जाएं, ताकि कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी न हो। खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव ने खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रभावी प्रवर्तन एवं सतत निगरानी को और मजबूत किए जाने के निर्देश दिए। इसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों की जांच के लिए टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़ाने तथा संबंधित मामलों के त्वरित निस्तारण पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को दी जा रही विशेष सहायता के अंतर्गत स्वीकृत सभी परियोजनाओं को गतिशक्ति पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराने के लिए नियमित और कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया। जन-जन की सरकार कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए मुख्य सचिव ने तहसील दिवस और थाना दिवसों का वर्षभर नियमित आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर बल दिया गया।

डिजिटल शासन की दिशा में ई-ऑफिस प्रणाली को लेकर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि इसे मुख्यालयों के साथ-साथ जनपद स्तर के कार्यालयों में प्रभावी रूप से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक सचिव समिति की बैठक में की जाएगी, जिसमें विभागीय सचिवों एवं जिलाधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा।

नक्शा पास प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नक्शा स्वीकृत करने वाली सभी प्राधिकरण, नक्शा पास होने के बाद संबंधित स्थानीय निकायों के साथ उसकी समस्त जानकारियां साझा करें, ताकि स्थानीय निकाय अपने डाटाबेस को अद्यतन कर सकें।

श्रमिक हितों को लेकर मुख्य सचिव ने कहा कि कुछ विभागों में लेबर कंप्लायंस टूल का प्रयोग एक सराहनीय पहल है। इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए, ताकि श्रमिकों से जुड़ी शिकायतों और समस्याओं का समाधान एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रभावी ढंग से किया जा सके।

जिला प्रशासन की सख्ती से शिमला बायपास पर सड़क निर्माण कार्य शुरू

पथ प्रवाह, देहरादून

शिमला बायपास रोड पर सड़क खुदाई के कारण आमजन को हो रही असुविधा एवं यातायात में बाधा की शिकायतों का जिलाधिकारी सविन बंसल ने तत्काल संज्ञान लिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल कुमार द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शिमला बायपास मार्ग पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) द्वारा की गई खुदाई के कारण सड़क की सतह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। स्थानीय नागरिकों द्वारा धूल, गड्ढों तथा जाम की गंभीर समस्या की शिकायत भी की गई।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए संबंधित विभागों को तत्काल सड़क मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क पुनर्स्थापन (रोड रेस्टोरेशन) का कार्य युद्धस्तर पर प्रारंभ कर दिया गया है।

जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की सड़क खुदाई के पश्चात निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं समयबद्ध ढंग से रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि विगत दिवस जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी करते हुए सड़क खुदाई से संबंधित समस्त अनुमतियां निरस्त कर दी गई हैं। बिना अनुमति सड़क खुदाई करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन आमजन की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक मार्गों की स्थिति पर सतत निगरानी बनाए हुए है।

एक नजर

बहादराबाद पुलिस ने खोली शातिर की हिस्ट्रीशीट

पथ प्रवाह, हरिद्वार। लगातार लड़ाई झगड़े, मारपीट, हत्या के प्रयास, बलवे, धोखाधड़ी जैसे अपराधों में लिप्त आदतन एक और अपराधी पर हरिद्वार पुलिस ने शिकंजा कसा है। एसएसपी के निर्देश पर आदतन अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। इन आदतन अपराधियों की प्रत्येक गतिविधि पर पुलिस अब हिस्ट्रीशीट खोलकर पैनी नजर रखेगी। एसएसपी हरिद्वार द्वारा गोकशी, मादक पदार्थों/ मादक द्रव्यो/ अवैध शस्त्रो /शराब की तस्करी/ लूट, चोरी, नकबजनी, एवं लडाई-झगडा एवं बलवा कर शांति व्यवस्था भंग करने वाले आदतन अपराधियों पर कार्रवाई किए जाने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। उपरोक्त क्रम में बहादराबाद पुलिस द्वारा आदतन अपराधियों पर कडी कार्यवाही करते हुए इस वर्ष पूर्व में दस अभियुक्तों की हिस्ट्रीशीट खोली जा चुकी है। इसी क्रम में थाना बहादराबाद द्वारा लगातार लड़ाई झगड़े, मारपीट, हत्या के प्रयास, बलवे, धोखाधड़ी जैसे अपराधों में लिप्त आदतन एक और अपराधी की हिस्ट्रीशीट खोलते हुए शिकंजा कसा गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हिस्ट्रीशीटर का नाम शहजाद अली पुत्र नईम निवासी राजपूतान थाना बहादराबाद जिला हरिद्वार है।

नैनीताल और टिहरी की टीम ने जीती फुटबॉल प्रतियोगिता

पथ प्रवाह, हरिद्वार। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के तहत फुटबॉल के अंडर-14 बालिका वर्ग में नैनीताल और टिहरी की टीम अंडर-19 वर्ग में जीती। सोमवार को अंडर-14 बालिका वर्ग के फुटबॉल इवेंट में नैनीताल ने पहला स्थान पाया। पौड़ी गढ़वाल की टीम दूसरे और हरिद्वार की टीम तीसरे स्थान पर रही। अंडर-19 बालिका वर्ग के फुटबॉल इवेंट में टिहरी गढ़वाल की टीम ने पहला स्थान पाया। हरिद्वार की टीम दूसरे और देहरादून की टीम तीसरे स्थान पर रही। विजेता और उपविजेता टीमों को उप क्रीड़ाधिकारी प्रदीप कुमार और मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रभारी मुकेश कुमार भट्ट ने पुरस्कृत किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी विकास चौधरी सहित आशीष, सोनू कुमार, संदीप खंखरियाल, अवनीश कुमार, पूनम मिश्रा, विमल सिंह लसपाल, रितेश चौहान, प्रियंका, जितेंद्र पुंडीर, मुदस्सिम, सुमित कुमार, अखिलेश मंडल, वंश, राहुल, विमल मौजूद रहे।

चोरों ने चोरी कर ली नगर निगम की हाईमास्ट लाइट चोरी

पथ प्रवाह, हरिद्वार। हरिद्वार में नगर निगम की हाई मास्टलाइट चोरी होने की घटना सामने आयी है। वार्ड-53 विष्णु लोक कॉलोनी के पास लगी हाईमास्ट लाइट और मोटर अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। सुबह जब लोगों की नजर इस पर गई तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल की। जानकारी के अनुसार यह हाईमास्ट लाइट 2024 में करीब लगाई गई थी। हाईमास्ट लाइट के पोल से लाइटें और मोटर चोरी कर लिया गया। चोरी की इस घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। चोरी होने की जानकारी मिलने पर सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद भी मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस को तहरीर दी जाएगी। नगर निगम यह भी जांचेगा कि चोरी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में कहां और कैसे चूक हुई। लाइट से सभी बल्ब और मोटर गायब है। स्थानीय पार्षद का कहना है कि इस लाइट के चोरी होने से यह मुख्य रास्ता अंधेरे में डूब गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी पूछताछ कर घटना के बारे में जानकारी जुटायी। पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

जनता के द्वार तक पहुंचा शासन, अभियान से जनता को मिल रही राहत

पथ प्रवाह, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित समाधान का मजबूत उदाहरण बनता जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से राज्य सरकार आम नागरिकों की समस्याओं को उनके नजदीक जाकर सुनने और समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। 08 फरवरी 2026 तक प्रदेश में 597 जनसुनवाई कैम्प आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें आज 8 कैम्प लगाए गए। इन कैम्पों में अब तक 4,68,778 नागरिकों ने अपनी समस्याएं और आवेदन प्रस्तुत किए, जबकि आज अकेले 4,822 नागरिकों ने सहभागिता दर्ज कराई। अभियान के तहत अब तक 46,296 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 31,242 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। आज के दिन प्राप्त 695 शिकायतों में से 519 शिकायतों का निस्तारण कर प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही का उदाहरण प्रस्तुत किया। कैम्पों के दौरान विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए 66,121 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 593 आवेदन आज प्राप्त किए गए। इसके अतिरिक्त विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत अब तक 2,60,312 नागरिकों को लाभान्वित किया गया, जिनमें आज 2,256 नागरिक शामिल हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी एवं उत्तरकाशी सहित सभी जनपदों में अभियान को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में बड़ी संख्या में नागरिकों की भागीदारी यह दर्शाती है कि जनता इस पहल पर भरोसा जता रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह अभियान शासन और जनता के बीच की दूरी को समाप्त करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत और आवेदन का शीघ्र, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए, जिससे आम नागरिकों का विश्वास शासन व्यवस्था में और अधिक सुदृढ़ हो।

विधायक आदेश चौहान ने किया आंतरिक सड़क और पुलिया निर्माण कार्य का शुभारंभ

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने नगरपालिका शिवालिकनगर अंतर्गत वार्ड नंबर 12 रामधाम कॉलोनी की रोशनपुरी कॉलोनी में आंतरिक सड़क एंव पुलिया के निर्माण का कार्य पूजन कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम मे बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों द्वारा विधायक आदेश चौहान का स्वागत किया गया।

इस अवसर पर रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि विकास कार्यो की गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई समझौता ना किया जाये। सरकार की विभिन्न योजनाओं से पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य प्रगति पर है। भाजपा सरकार क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। क्षेत्र के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार धन की कमी नहीं रहने दी जाएगी। जनता को मूलभूत सुविधाओं का और भी बेहतर लाभ दिलाने का भाजपा सरकार का वायदा लगातार धरातल पर नजर आ रहा है। सांसद प्रतिनिधि अतुल वशिष्ठ ने कहा कि रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने क्षेत्र के विकास कार्यो में नया कीर्तिमान स्थापित किया है।उनकी कार्यप्रणाली से योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य धरातल पर नजर आ रहे हैं। स्थानीय सभासद गरिमा सिंह ने रानीपुर विधायक का धन्यवाद करते हुए कहा कि विकास कार्यों के दृष्टिकोण से नई बसी कॉलोनियों में ही कई करोड रूपए की लागत से पिछले कुछ समय में ही विभिन्न विकास कार्य हुए हैं।उनकी कार्यप्रणाली अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक प्रेरणा है। कार्यक्रम में अश्वनी कुमार, सतपाल सिंह, संजीव चौहान, नीटू कुमार, कमलाकर शास्त्री, सूरज नेगी, ललित कुमार, प्रीतम, भूरा कुमार, सौरभ सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

पुलिस लाइन उत्तरकाशी का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण, व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी।

पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी जनक सिंह पंवार द्वारा सोमवार, 9 फरवरी 2026 को पुलिस लाइन उत्तरकाशी का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम क्वार्टर गार्ड का निरीक्षण करते हुए गार्ड में तैनात पुलिस कर्मियों के टर्न-आउट एवं शस्त्र कवायद की गहन जांच की गई।

इसके उपरांत पुलिस उपाधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं–भोजनालय, शस्त्रागार, स्टोर, पोलनेट, डीसीआर, एमटी, गणना शाखा, जीडी, कैश कार्यालय, पुलिस कैंटीन, जिम, मनोरंजन कक्ष, शिकायत प्रकोष्ठ, सीसीटीएनएस एवं एएचटीयू–की साफ-सफाई, अभिलेखों एवं कार्यप्रणाली का बारीकी से अवलोकन करते हुए समीक्षा की गई। साथ ही लाइन परिसर एवं बैरिकों की स्वच्छता का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि पुलिस लाइन परिसर में उपलब्ध आपदा उपकरणों को सदैव चालू अवस्था में रखा जाए तथा पुलिस कर्मियों को समय-समय पर उपकरणों की हैंडलिंग एवं ऑटोमैटिक वेपन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाए। इसके अतिरिक्त मैस में भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा साप्ताहिक चार्ट के अनुसार भोजन परोसने के भी निर्देश दिए गए।

स्कूल और अस्पताल जलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा:अमित शाह

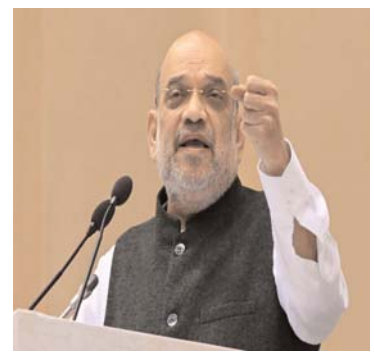

जगदलपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में आयोजित तीन दिवसीय संभाग स्तरीय बस्तर पण्डुम के समापन समारोह में कहा कि सरकार बस्तर की संस्कृति को आने वाले दशकों तक सुरक्षित रखना चाहती है। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी का लक्ष्य बस्तर की संस्कृति और विरासत को विश्व पटल तक पहुंचाना है, ताकि इसकी पहचान बंदूक और विस्फोटकों से नहीं बल्कि परंपरा से हो। शेष बचे कई नक्सलियों में युवा आदिवासी लड़कियां भी शामिल हैं, उनका पुनर्वास जरूरी है क्योंकि उनका पूरा जीवन आगे पड़ा है। अमित शाह ने नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की माओवादी पुनर्वास नीति सबसे आकर्षक है। जो लोग गोली चलाना, स्कूल और अस्पताल जलाना जारी रखेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, हिंसा का कड़ा जवाब मिलेगा। माओवाद ने समाज को कभी लाभ नहीं पहुंचाया, जहां भी रहा वहां विनाश ही हुआ, कोलंबिया, पेरू, कंबोडिया जैसे देशों में भी यही देखा गया। शाह के बस्तर आगमन पर हजारों स्कूली बच्चों ने ऐसा जादू है मेरे बस्तर में गीत पर सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर उनका स्वागत किया। यह गीत बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है और इसे हिंदी व हल्बी बोली में रचा गया है।

बस्तर सबसे विकसित संभाग बनेगा

गृह मंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जनजातीय कलाकारों को मंच देकर बस्तर की संस्कृति को नया जीवन दिया है और अब यह क्षेत्र विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर को सबसे विकसित संभाग बनाया जाएगा। नक्सलवाद खत्म होते ही नई पर्यटन गतिविधियां शुरू होंगी। बस्तर में 118 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिससे आदिवासी युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं रावघाट योजना भी तेजी से आगे बढ़ रही है और इससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। शाह ने भरोसा दिलाया कि बस्तर को प्रदेश का सबसे विकसित संभाग बनाया जाएगा। उन्होंने ये बातें जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित बस्तर पंडुम के मंच से कही। इससे पहले स्वागत के दौरान उन्हें कौड़ी की माला और पारंपरिक पगड़ी पहनाई गई। अमित शाह ने कहा कि बस्तर की पहचान बारूद नहीं, बल्कि उसकी समृद्ध संस्कृति और कला है। बस्तर पंडुम पहले 7 विधाओं तक सीमित था, लेकिन अब 5 नई विधाएं जुड़ने से यह 12 विधाओं का उत्सव बन गया है। उन्होंने कहा कि बस्तर की कला और संस्कृति विश्व में अद्वितीय है, जिसे प्रभु श्रीराम के समय से संजोकर रखा गया है। आयोजन में करीब 55 हजार लोगों ने भाग लिया, जिसमें दंतेवाड़ा से सबसे अधिक सहभागिता रही और अबूझमाड़िया, माड़िया व मुरिया जनजातियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन की सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी से मुलाकात

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन की सोमवार को नई दिल्ली में सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी से मुलाकात हुई।

बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत-सेशेल्स द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की और दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने का उल्लेख किया। उन्होंने समुद्री सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, चिकित्सा, उच्च शिक्षा, आतिथ्य सत्कार और डिजिटलीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और मज़बूत करने के अवसरों पर विचार-विमर्श किया। उपराष्ट्रपति ने पिछले वर्ष अक्टूबर में सेशेल्स की अपनी यात्रा का स्मरण किया, जब उन्होंने राष्ट्रपति हर्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था।

दोनों नेताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा दृष्टिकोण की पुष्टि की।

जनसुनवाई में गूंजा पीड़ितों का दर्द, जिलाधिकारी ने दिलाया न्याय व सुरक्षा का भरोसा

पथ प्रवाह, देहरादून

जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जनता दरबार का आयोजन कर जनसमस्याओं का निस्तारण किया गया। जनता दरबार में उपस्थित फरियादियों ने भूमि विवाद, निजी भूमि का सीमांकन, अवैध कब्जा, आपसी विवाद, आर्थिक सहायता, रोजगार, शिक्षा, एडीए, नगर निगम से संबंधित कुल 195 शिकायतें एवं समस्याएँ जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कीं। जिलाधिकारी ने सभी जनशिकायतों एवं समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी के समक्ष आयोजित जनसुनवाई में समाज के कमजोर, बुजुर्ग और पीड़ित वर्ग की समस्याएँ स्पष्ट रूप से सामने आईं। जिलाधिकारी ने प्रत्येक शिकायत को संवेदनशीलता से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित तथा प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं, बुजुर्गों और कमजोर वर्ग के सम्मान

एवं सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

अम्बीवाला निवासी नेशनल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी विजय चौधरी ने बताया कि उनकी माता कलावती के नाम दर्ज भूमि पर विवाद न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद पड़ोसी महिला द्वारा उनकी भूमि पर लगे हरे-भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने मौके पर ही एसडीएम को निर्देश दिए कि न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक भूमि में यथास्थिति बनाए रखी जाए।

भूतपूर्व सैनिक राजेश कुमार ने शिकायत की कि वर्ष 2016 में खरीदी गई उनकी भूमि पर मूल खातेदारों में से एक ने अवैध कब्जा कर रखा है और भ्रामक जानकारी देकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जिलाधिकारी ने मौके पर ही एसडीएम एवं तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट में विपक्षी की कार्रवाई को निराधार पाया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने एसडीएम विकासनगर को शिकायतकर्ता को भूमि पर कब्जा दिलाने के निर्देश दिए।

डोईवाला निवासी मीना क्षेत्री ने अपने पुत्र व पुत्रवधू से जान-माल का खतरा बताते हुए शिकायत दर्ज कराई। मामला तहसील में लंबित होने पर जिलाधिकारी ने इसे तत्काल जिला कार्यालय में स्थानांतरित कर फास्ट ट्रैक सुनवाई कराने के निर्देश दिए।

जौलीग्रांट निवासी बुजुर्ग विधवा लक्ष्मी तोमर ने बताया कि उनके दिवंगत पति शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त थे। उपचार के दौरान दिए गए ?1.37 लाख के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। जिलाधिकारी ने शिक्षा अधिकारी से आज ही स्पष्ट आख्या तलब की।

एटनबाग के काश्तकारों ने सिंचाई नहर पर अवैध निर्माण के कारण खेतों की सिंचाई में आ रही कठिनाई से अवगत कराया। इस पर अधिशासी अभियंता को दो दिन के भीतर जांच कर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए गए।

डालनवाला क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर द्वारा फर्जी जमीन दिखाकर ?8 लाख की ठगी की शिकायत पर क्षेत्राधिकारी पुलिस को त्वरित व कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। ऋषिकेश निवासी बुजुर्ग छज्जू राम ने पुत्रवधू द्वारा मारपीट और घर से निकालने के दबाव की शिकायत की, जिस पर क्षेत्राधिकारी पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

हरिपुर कलां निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी निजी भूमि व सरकारी सड़क पर अवैध कब्जे की शिकायत की। जिलाधिकारी ने एसडीएम को जांच कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कारगी चौक, कुंज विहार निवासी ममता नौटियाल ने बताया कि उनकी गली में सीवर लाइन बिछाई गई, लेकिन उनका घर छोड़ दिया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित संस्था को तत्काल कार्रवाई कर समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए। डोईवाला निवासी दीपा द्वारा कानूनी सलाह एवं मुकदमे में सहायता हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की मांग पर मामला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित किया गया।

जनता दरबार में अपर जिलाधिकारी(वि.रा) केके मिश्रा, एसडीएम अपूर्वा सिंह, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएम विनोद कुमार, उप नगर आयुक्त संतोष कुमार पांडेय, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार सहित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

एक नजर

मेयर पद की प्रबल दावेदार रही पार्षद मोनिका सैनी के जन्मदिन पर बधाई देने वालों का लगा तांता

पथ प्रवाह, हरिद्वार। नगर निगम हरिद्वार के वार्ड संख्या 19 से भारतीय जनता पार्टी की पार्षद एवं मेयर पद की प्रबल दावेदार रही श्रीमती मोनिका सैनी के जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। जन्मदिन के मौके पर पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं। इस अवसर पर समर्थकों ने उनके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करते हुए कहा कि श्रीमती मोनिका सैनी जनसेवा के प्रति समर्पित और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं। उनके नेतृत्व में वार्ड संख्या 19 सहित नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को नई दिशा मिली है। जन्मदिन के अवसर पर पूरे दिन उनके आवास एवं कार्यालय पर बधाई देने वालों का आना-जाना लगा रहा।

जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसद चुनाव में किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

टोक्यो। जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के नेतृत्व वाली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ने संसद के महत्वपूर्ण निचले सदन के चुनावों में शानदार जीत प्राप्त की, जिसमें उसने दो-तिहाई से अधिक यानी 465 में से 316 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो दो दशकों में एलडीपी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पार्टी को विधेयकों को पारित करने में मदल मिलेगी, भले ही वे ऊपरी सदन में वह खारिज हो जाएं जहां पार्टी के पास बहुमत नहीं है और इसके लिए उसे अन्य राजनीतिक दलों के सांसदों के वोटों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। स्पुतनिक द्वारा एलडीपी के परिणामों के विश्लेषण के आधार पर, यह पिछले 20 वर्षों में इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले, पार्टी ने जुनिचिरो कोइजुमी के नेतृत्व में 2025 में (296 सीटें) और शिंजो आबे के नेतृत्व में 2012 में (294 सीटें) सीटें प्राप्त की थीं।

रविवार को हुए मतदान के लिए चुनाव आयोग के आंकड़े प्रमुख टेलीविजन नेटवर्कों पर लाइव प्रसारित किए गए। एलडीपी के सहयोगी जापान इनोवेशन पार्टी ने 36 सीटें जीतीं हैं जिससे एलडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन पास अब 465 सीटों में से 352 सीटें हो गई हैं।

हिमाचल में वित्तीय संकट के बीच कांग्रेस की गारंटी की खुली पोल : जयराम ठाकुर

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेतृत्व और मुख्यमंत्री पर तीखा हमला करते हुए सवाल उठाया कि क्या सरकार लोगों को झूठे एवं अवास्तविक आश्वासन देते समय राज्य की वित्तीय स्थिति से अनजान थी। उन्होंने सोमवार को नगरोटा बागवान में पार्टी प्रचार के दौरान कहा, 'कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बार-बार दावा किया कि उनके पास एक स्पष्ट कार्ययोजना है, उन्होंने सभी आवश्यक शोध कर लिए हैं और उन्हें पता है कि वादे कैसे पूरे किए जाएंगे। हालांकि मौजूदा वित्तीय संकट ने इन दावों की पोल खोल दी है। उन्होंने याद दिलाया कि एक सप्ताह पहले तक मुख्यमंत्री 'तथाकथित व्यवस्थागत परिवर्तनों' के माध्यम से राज्य को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की बात कर रहे थे। विपक्ष ने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री उस समय राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति से अनजान थे। इस स्थिति को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए, श्री ठाकुर ने कहा कि तीन साल से अधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने के बाद भी, वादों को पूरा करने की उम्मीदें जगाते रहना गंभीरता एवं विश्वसनीयता की कमी को दर्शाता है। भाजपा नेता ने मांग करते हुए कहा कि सरकार को खोखले दावे करने के बजाय राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए और सुशासन एवं वित्तीय अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

अमित शाह करेंगे साइबर-धोखाधड़ी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन

सीबीआई की नई साइबर शाखा भी लॉन्च

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, अमित शाह मंगलवार, 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में 'Tackling Cyber-Enabled Frauds & Dismantling the Ecosystem' (साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से निपटने और इसके ईकोसिस्टम) को ध्वस्त करने विषय पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री इस अवसर पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) अधिकारियों के अलंकरण समारोह की अध्यक्षता करेंगे और ब्यूरो की नई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन करेंगे। वे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (IyC) के राज्य अपराध समन्वय केंद्र (SyC) डैशबोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे।

साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से निपटने और इसके ईकोसिस्टम को ध्वस्त खत्म करने विषय पर दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन 10 और 11 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में CBI द्वारा गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (IyC) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) वर्ष 2000 से साइबर अपराधों की जांच कर रही है और उसने 2022 में साइबर साइबर अपराध जांच प्रभाग स्थापित कर अपनी क्षमताएं उन्नत की हैं। यह प्रभाग सरकार और उसके कार्यालयों को प्रभावित करने वाले साइबर अपराधों की जांच के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है। साइबर अपराध जांच प्रभाग साइबर-आधारित अपराधों और साइबर-सक्षमता धोखाधड़ी दोनों की जांच करता है।

यह सम्मेलन ऐसे समय आयोजित हो रहा है, जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में तीव्रता से हुए डिजिटल बदलाव से बैंकिंग, शासन और संचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हालांकि इसके साथ ही नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं जिसका फायदा संगठित साइबर अपराधी नेटवर्क उठा रहे हैं।

सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में साइबर-सक्षम धोखाधड़ी की व्यापकता, रुझान और बदलते स्वरूप को पहचानना; साइबर-धोखाधड़ी ईकोसिस्टम के तीन महत्वपूर्ण स्तंभों की जांच करना, जिनमें वित्तीय स्तंभ (धनशोधन, धोखाधड़ी और अवैध धन हस्तांतरण सहित वित्तीय अपराधों को अंजाम देने में इस्तेमाल होने वाले बैंक खाते - म्यूल अकाउंट तथा धनशोधन), टेलीकॉम स्तंभ (सिम और ई-सिम और डिजिटल ढांचे का दुरुपयोग), और मानव स्तंभ (साइबर गुलामी और मानव तस्करी से बनाए गये स्कैम परिसर); कानून प्रवर्तन, बैंकों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, विनियामक और प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के बीच अंतर-एजेंसी समन्वय और सार्वजनिक-निजी सहयोग सुदृढ़ करना; सीमित मानव बल के साथ जांच आगे बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के इस्तेमाल की संभावना पर विचार; साइबर धोखाधड़ी की जल्द रिपोर्टिंग, धोखाधड़ी के धन की रियल-टाइम निगरानी, समय पर सबूतों के संरक्षण और पीड़ित सुरक्षा तंत्र में सुधार करना शामिल हैं।

यह सम्मेलन रोकथाम, जांच, प्रौद्योगिकी अपनाने, अंतर-एजेंसी तालमेल और पीड़ित केंद्रित व्यवस्था सुदृढ़ कर साइबर सक्षम धोखाधड़ी से निपटने के लिए एकीकृत रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास है। अंततः, इसका लक्ष्य लोगों को साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षित बनाना, आपराधिक ढांचे ध्वस्त करना और भारत के डिजिटल परितंत्र के प्रति जन-विश्वास मज़बूत बनाना है।

दो दिन के सम्मेलन में केंद्र और राज्य की कानून प्रवर्तक एजेंसियों, दूरसंचार विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सरकारी, निजी और सहकारी क्षेत्र के बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक - नाबार्ड, फिनटेक कंपनियों और पेमेंट प्लेटफॉर्म, दूरसंचार सेवा प्रदाता, सोशल मीडिया और क्लाउड सर्विस इंटरमीडियरी (मध्यस्थ), साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, डोमेन विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी और पॉलिसी प्रतिनिधियों के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। बहुपक्षीय जुड़ाव वाला यह सम्मेलन साइबर अपराध से निपटने के संपूर्ण पारितांत्रिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में हेलेनिक गणराज्य के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की

रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त आशय घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए

नई दिल्ली । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली में हेलेनिक गणराज्य के रक्षा मंत्री निकोलाओस-जॉर्जियोस डेंडियास के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने भारत-ग्रीस रणनीतिक साझेदारी शांति, स्थिरता, स्वतंत्रता और पारस्परिक सम्मान के साझा मूल्यों पर आधारित होने की बात दोहराई।

दोनों देशों ने भारत के आत्मनिर्भर भारत और एजेंडा 2030 के तहत ग्रीस के रक्षा सुधारों के बीच साझेदारी के माध्यम से अपने-अपने स्वदेशी रक्षा उद्योगों की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया। भारत और ग्रीस के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, यह पांच वर्षीय रोडमैप तैयार करने का प्रारंभिक बिंदु है।

रक्षा मंत्रियों ने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और द्विपक्षीय रक्षा

सहयोग और रणनीतिक सम्बंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। 2026 के लिए एक द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना का भी आदान-प्रदान किया गया। इसमें दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सैन्य गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की गई है।

दोनों प्राचीन समुद्री राष्ट्रों के बीच विभिन्न प्रमुख समुद्री मुद्दों पर सहमति का भी उल्लेख किया गया। ग्रीस की ओर से गुरुग्राम स्थित सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर) में एक ग्रीक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की घोषणा की गई।

बैठक से पहले, ग्रीस के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मानेकशॉ केंद्र में त्रि-सेवा गार्ड ऑफ ऑनर का भी निरीक्षण किया।

इस यात्रा के दौरान, हेलेनिक प्रतिनिधिमंडल ने बेंगलुरु में प्रमुख रक्षा एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों का दौरा किया और साथ ही नई दिल्ली में रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू), रक्षा उद्योग और स्टार्टअप प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। यह यात्रा दोनों देशों की सरकारों और लोगों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंधों पर आधारित भारत और हेलेनिक गणराज्य के बीच रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि करती है।

एक नजर

सीएम हिमंता पर दर्ज हुई एफआईआर

हैदराबाद(ईएमएस)। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ हैदराबाद पुलिस में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत असम भाजपा द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के संदर्भ में की गई है, जिसे अब डिलीट कर दिया गया है। ओवैसी का आरोप है कि इस वीडियो में मुख्यमंत्री को मुसलमानों को शूट करते हुए दिखाया गया था, जिसे उन्होंने हिंसक और भड़काऊ बताया है। ओवैसी ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से इस मामले में सीएम सरमा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए ओवैसी ने कहा कि दुर्भाग्य से नरसंहार वाले नफरती भाषण अब एक सामान्य बात बन गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक, जिस वीडियो को लेकर विवाद शुरू हुआ है, उसे असम भाजपा के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किया गया था। हालांकि, विवाद बढ़ने और तीखी प्रतिक्रियाओं के बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया है। ओवैसी का दावा है कि वीडियो में दिखाई गई सामग्री न केवल हिंसक थी, बल्कि मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रही थी।

शरद पवार अस्पताल में हुए भर्ती

पुणे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) प्रमुख शरद पवार को पुणे के रूबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें गले में संक्रमण और बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। बताया गया है कि पवार पहले बारामती में थे और वहीं प्राथमिक इलाज लिया था, लेकिन तबीयत पूरी तरह ठीक न होने पर उन्हें आगे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। अस्पताल में उनकी बेटी और एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले और दामाद सदानंद सुले मौजूद हैं। हाल के दिनों में भतीजे अजित पवार के निधन के बाद शरद पवार लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में सक्रिय थे, जिससे उनकी तबीयत पर असर पड़ा माना जा रहा है। फिलहाल डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

संसद और स्कूलों में बम की धमकी

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के 9 स्कूलों को सोमवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिले। मेल में दावा किया गया कि 13 फरवरी को दोपहर 1.11 बजे संसद में ब्लास्ट होगा और दिल्ली को खालिस्तान बना देंगे। ईमेल में आतंकी अफजल गुरु और पंजाब को खालिस्तान बताने का भी जिक्र था। धमकी के बाद स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, सुबह अलग-अलग इलाकों के स्कूलों से इमरजेंसी कॉल आई। इसके बाद फायर टेंडर, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड तुरंत मौके पर पहुंची। धमकी भरे ईमेल में लिखा है कि अफजल गुरु की याद में दिल्ली बनेगा खालिस्तान। 1:11 बजे पर धमाका होगा, 13 फरवरी को 1:11 बजे पर संसद में ब्लास्ट होगा। पंजाब खालिस्तान है। खालिस्तान नेशनल आर्मी। डीएफएस के एक अधिकारी ने कहा कि अब तक 9 स्कूलों ने बम की धमकी मिलने की सूचना दी है। सभी परिसरों की जांच की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ईमेल की लोकेशन और सोर्स पता करने के लिए साइबर टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। साथ ही राजधानी के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। अब तक किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।

सोनम वांगचुक मामले पर सुनवाई टली

नई दिल्ली। सोनम वांगचुक की हिरासत मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। जस्टिस जे कुमार ने एडीशनल सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि केस में कोई प्रोग्रेस है। उन्होंने जवाब दिया कि अभी कोई प्रोग्रेस नहीं है। इसके बाद सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज दूसरे मामले में बिजी हैं। जिस वजह से सुनवाई नहीं हो सकी।

थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार

नई दिल्ली। तमिलनाडु के मदुरै स्थित थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी से जुड़े धार्मिक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सोमवार 9 फरवरी को न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें नल्लिथोप्पू क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय को केवल रमजान और बकरीद के अवसर पर ही नमाज अदा करने की अनुमति दी गई है। साथ ही वहां कुर्बानी देने और मांसाहारी भोजन से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक जारी रहेगी।

यह मामला याचिकाकर्ता एम. इमाम हुसैनी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका से जुड़ा था, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि धार्मिक सौहार्द और विभिन्न पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए नल्लिथोप्पू इलाके में नमाज की अनुमति केवल दो प्रमुख त्योहारों तक सीमित रखी जाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि मद्रास हाईकोर्ट का आदेश संतुलित और व्यावहारिक प्रतीत होता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट और प्रिवी काउंसिल पहले ही यह मान चुके हैं कि नल्लिथोप्पू की लगभग 33 सेंट भूमि मुस्लिम समुदाय की है। इसके बावजूद नमाज की अनुमति को सिर्फ रमजान और बकरीद तक सीमित करना समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर अनुचित प्रतिबंध है। प्रशांत भूषण ने यह भी तर्क दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है और उस पर इस तरह की पाबंदियां न्यायसंगत नहीं हैं। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि फैसला सभी समुदायों के हितों और क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर दिया गया है।

बाबा सिद्दीकी हत्या मामले के आरोपी आकाशदीप को मिली सशर्त जमानत

मुंबई। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोमवार 9 फरवरी को इस केस के आरोपी आकाशदीप करज सिंह को सशर्त जमानत दी है। आकाशदीप इस मामले में जमानत पाने वाला पहला आरोपी है। न्यायमूर्ति नीला गोखले की एकल पीठ ने जमानत देते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक आरोपी मुंबई नहीं छोड़ेगा। बता दें कि 12 अक्टूबर 2024 की रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में बाबा सिद्दीकी (66) की उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात को तीन हमलावरों ने अंजाम दिया था। मुंबई पुलिस ने इस मामले में पंजाब निवासी आकाशदीप करज सिंह (22) को नवंबर 2024 में गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका में आकाशदीप सिंह ने खुद को निर्दोष बताते हुए दावा किया था, कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में महायुति ने किया जोरदार प्रदर्शन

मुंबई। महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने जोरदार प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक, महायुति ने 12 जिला परिषदों की कुल 731 सीटों में से 552 सीटों पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बढ़त बना ली है। यह जीत राज्य की सियासत में महायुति की मजबूत पकड़ का संकेत मानी जा रही है। फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से पूर्ण आंकड़े जारी होना बाकी है।

7 फरवरी को हुए 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनावों की मतगणना सोमवार को की गई। जिला परिषदों में रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव और लातूर सीट शामिल हैं। इन जिला परिषदों के साथ ही इनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली 125 पंचायत समितियों की 1,462 सीटों पर भी मतदान हुआ था।

इन चुनावों में कुल 68. 28 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। मतदाताओं को दो वोट डालने थे। एक जिला परिषद सीट के लिए और दूसरा पंचायत समिति के चुनाव क्षेत्र के लिए। चुनाव प्रक्रिया में जिला परिषद के लिए सफेद बैलेट पेपर और पंचायत समिति के लिए गुलाबी बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया। खास बात यह भी रही कि कोंकण क्षेत्र, जिसे ठाकरे परिवार का पारंपरिक गढ़ माना जाता रहा है, वहां भी महायुति को समर्थन मिला। इसे राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

इन चुनावों के नतीजे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के भविष्य की दिशा तय करने में भी अहम माने जा रहे हैं। अजित पवार और शरद पवार गुट ने दो साल की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को किनारे रखते हुए पुणे, सतारा, सोलापुर और सांगली में स्थानीय निकाय चुनावों में अनौपचारिक गठबंधन किया था। इन क्षेत्रों में दोनों गुटों के उम्मीदवारों ने मूल 'घड़ी' चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा।

पाक एजेंट आरोप पर बोले गौरव गोगोई— मुझे मजबूर किया गया तो चुप नहीं रहूंगा

गुवाहाटी। असम में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर लगाए गए 'पाकिस्तान कनेक्शन' के आरोपों पर अब गोगोई ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान को न सिर्फ अस्वीकार्य बताया, बल्कि इसे राजनीतिक शिष्टाचार की सभी सीमाओं को पार करने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि मुझे मजबूर किया तो फिर मैं चुप नहीं रहूंगा।

दरअसल, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गौरव गोगोई की वर्ष 2013 की पाकिस्तान यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उनके वीजा में लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जाने की अनुमति थी, जबकि उन्होंने तक्षशिला का दौरा किया, जो पंजाब के रावलपिंडी जिले में स्थित है। मुख्यमंत्री सरमा ने यह भी कहा कि रावलपिंडी एक हाई-सिक्योरिटी क्षेत्र है, जहां पाकिस्तानी सेना का जनरल हेडक्वार्टर (जीएचक्यू) मौजूद है और वहां आम नागरिकों का प्रवेश आसान नहीं होता। ऐसे में यह दौरा किसी संस्थागत व्यवस्था के बिना संभव नहीं हो सकता। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया।

इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस एसआईटी रिपोर्ट का हवाला दिया था, उसे छह महीने तक दबाकर रखा गया, क्योंकि सरकार उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करने में असफल रही।

गोगोई ने सवाल किया कि यदि यह मामला वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा था, तो मुख्यमंत्री इतने समय तक चुप क्यों बैठे रहे। गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि असम में कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जब हमने मुख्यमंत्री के परिवार के पास कथित रूप से 12 हजार बीघा जमीन होने का मुद्दा उठाया, तभी से यह पूरा नाटक शुरू हुआ। उन्होंने पाकिस्तान से किसी भी तरह के संबंधों के दावों को सिरे से खारिज किया।

मुख्यमंत्री द्वारा उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न और पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के साथ संबंधों के आरोप पर भी गोगोई ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी काम के सिलसिले में पाकिस्तान गई थीं और वह 2013 में 10 दिन की सामान्य यात्रा पर उनके साथ गए थे, जिसमें कुछ भी गुप्त या गैरकानूनी नहीं था। गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री पर उनके नाबालिग बच्चों को राजनीति में घसीटने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई नेताओं के बीच होनी चाहिए, बच्चों को इसमें शामिल करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, मुझे ऐसी स्थिति में मजबूर न करें, जहां मुझे जवाब देना पड़े। गोगोई ने यह भी कहा कि यह मामला इतना गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए।

गणतंत्र दिवस परेड में प्रोटोकॉल उल्लंघन के चलते दो आईपीएस अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी; जांच के आदेश

देहरादून। उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व की गरिमा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। गणतंत्र दिवस पर आयोजित पुलिस परेड के दौरान अनुशासन और निर्धारित प्रोटोकॉल की अनदेखी के आरोप में राज्य के दो आईपीएस अधिकारियों पर गाज गिरी है। पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए औपचारिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।

जांच के दायरे में आए अधिकारियों में हरिद्वार में तैनात आईपीएस जितेंद्र मेहरा और देहरादून में कार्यरत आईपीएस कुश मिश्रा शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित पुलिस परेड में सभी राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए सेरेमोनियल यूनिफॉर्म पहनकर शामिल होना अनिवार्य होता है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय पर्व की गरिमा, अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से तय की गई है। बताया जा रहा है कि आईपीएस जितेंद्र मेहरा ने इस नियम का पालन नहीं किया। वह गणतंत्र दिवस परेड में सेरेमोनियल यूनिफॉर्म की बजाय सामान्य ड्यूटी यूनिफॉर्म पहनकर पहुंचे। इसे स्पष्ट रूप से प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना गया है। अब जांच के दौरान उनसे यह स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि उन्होंने निर्धारित यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी और इसके पीछे क्या कारण रहे।

वहीं दूसरा मामला देहरादून में तैनात आईपीएस कुश मिश्रा से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेना ही जरूरी नहीं समझा और कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि कुश मिश्रा हाल ही में देहरादून में तैनात हुए हैं। इससे पहले भी उनके खिलाफ दो अलग-अलग मामलों की जांच हो चुकी है। इनमें जनपद पौड़ी में एक राजनीतिक नेता की पार्टी के दौरान पुलिस दबिश का मामला और एक चौकी परिसर में मारपीट से जुड़ा प्रकरण शामिल है, जिनकी जांच रिपोर्ट पहले ही पुलिस मुख्यालय को सौंपी जा चुकी है।

गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों को लेकर अधिकारियों की अनुपस्थिति और लापरवाही को लेकर पहले से ही चर्चाएं चल रही थीं। लोकभवन में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में भी कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल न होने की बातें सामने आई थीं। ऐसे में अब दो आईपीएस अधिकारियों से जुड़े इस मामले के उजागर होने के बाद पुलिस महकमे में हलचल और तेज हो गई है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों प्रकरणों को गंभीरता से लिया गया है। संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और यह जांच की जाएगी कि उन्होंने किन परिस्थितियों में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। इस पूरे मामले की जांच आईजी मुख्यालय डॉ. सदानंद दाते को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

पटना पहुंचे नितिन नवीन बोले- आज की पीढ़ी कल्पना भी नहीं कर सकति कि जंगलराज में काम करना कितना मुश्किल था

पटना। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सोमवार 9 फरवरी को नितिन नवीन पहली बार पटना पहुंचे। इस अवसर पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बापू सभागार में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए नितिन नवीन भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि वह किन शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त करें, यह समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जताए गए भरोसे के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वह इस जिम्मेदारी पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास करेंगे।

अपने संबोधन के दौरान नितिन नवीन ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जंगलराज के दौर में काम करना कितना मुश्किल था, यह आज की पीढ़ी शायद कल्पना भी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, उस समय कार्यकर्ता घर-घर चुपचाप पर्चियां पहुंचाते थे। डर और अराजकता का माहौल था। हम लोगों ने बिहार को उस जंगलराज से निकालकर यहां तक पहुंचाया है। नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने बिहार को विकास और सुशासन की राह पर आगे बढ़ाया है। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए बताया कि वर्ष 2006 में पिता के निधन के बाद वह राजनीति में आए थे और अब लगभग 20 साल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने माता-पिता से मिले संस्कारों ने यहां तक पहुंचाया है और वह उन्हें नमन करते हैं।

यहां नितिन नवीन ने कहा, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अब सिर्फ यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि बिहार का लड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है, बल्कि संगठन को और मजबूत करने के लिए जमीन पर काम करना होगा। कार्यक्रम में मौजूद बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नितिन नवीन का इस पद पर पहुंचना बिहार के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में 202 सीटों की जीत के बाद यह जिम्मेदारी मिलना पार्टी की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया और कहा कि अगला लक्ष्य पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और केरल में भाजपा की सरकार बनाना है।

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र के लिए काम करती है, जहां केवल सदस्यता नहीं बल्कि संबंध मायने रखते हैं।

स्वामी/प्रकाशक वीरेन्द्र सिंह ने मुद्रक प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कराकर, मुख्य कार्यालयः 40 शांतिपुरम कॉलोनी जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड 249408 (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया। वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) 9411111733, डॉ सुशील शर्मा(उप संपादक) 9837906777 किसी भी वाद विवाद का निपटारा हरिद्वार में होगा। वेबसाईट- www.pathpravah.com